

दिल्ली से प्रकाशित

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति पीएसयू और अपराध पर केंद्रित पत्रिका



**महायुद्ध की
दस्तक !**



SHREE JI CONSTRUCTION

AA CLASS GOVERNMENT CONTRACTOR



01, JAT MOHALLA, KAKROLIYA GHATI,
TEH. KOTRI, BHILWARA 311 601



097842 95060



SHREEJICONSTRUCTION777@GMAIL.COM



नागेश खान
संपादक

होर्मुज इफेक्ट से कई देश होंगे प्रभावित

ईरान-इजरायल युद्ध के चलते पश्चिम एशिया के हालात की वजह से तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसका नतीजा मार्केट पर दिखने लगा है। लेकिन, इसके बीच एक और संकट गहरा रहा है – उर्वरक आपूर्ति में कमी। अगर यह बाधा लंबे समय तक जारी रहती है तो दुनिया को खाद्य असुरक्षा और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम एशिया दुनिया का एक बड़ा उर्वरक उत्पादक क्षेत्र है। वैश्विक यूरिया निर्यात का लगभग 35: होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से दुनिया का 45: सल्फर भी ट्रांसपोर्ट होता है। यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है, जिसकी वजह से दुनिया का करीब आधा अनाज पैदा होता है। होर्मुज पर ईरान की पहरेदारी के चलते शिपमेंट का आना-जाना बंद है और हर बीतते दिन के साथ सप्लाई चेन टूट रही है। करीब 4 साल पहले, जब यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ था, तब भी इसी तरह की सिचुएशन बनी थी। उस वक्त दो बड़े झटके लगे थे – गेहूं की आपूर्ति में कमी और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में तेज उछाल। यूक्रेन और रूस मिलकर गेहूं का करीब 30: ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं, जिस पर उस समय एकदम से रोक लग गई थी। हालांकि तब जल्द ही रूस से दोनों चीजों का निर्यात जारी रहा। वहीं, भारत जैसे देशों ने गेहूं निर्यात बढ़ा दिया। लेकिन, इस बार सीधे समुद्री मार्ग बाधित होने से स्थिति दूसरी है। ईरान ने जिस तरह से दूसरे अरब देशों में मौजूद फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, उससे भी असर पड़ा है। समुद्र के रास्ते होने वाले यूरिया के कुल व्यापार में कतर एनर्जी की हिस्सेदारी लगभग 10: है। इसके एक कॉम्प्लेक्स पर दो दिन पहले ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने सल्फर, अमोनिया और यूरिया का प्रॉडक्शन रोक दिया है। ईरान और सऊदी अरब की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। फर्टिलाइजर मार्केट शुरू से बेहद संवेदनशील रहा है। चीन जैसे मुल्क अपनी जरूरत को देखते हुए ग्लोबल सप्लाई को प्रभावित करते हैं। नैचुरल गैस भी बड़ा फैक्टर है, जिसकी जरूरत फर्टिलाइजर प्रॉडक्शन में पड़ती है और जिसमें कमी आई है। भारत ने पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच रेकॉर्ड 70 लाख टन यूरिया आयात किया था। देश अपनी जरूरत का करीब 40: फर्टिलाइजर पश्चिम एशिया से मंगाता है, यानी उसके लिए स्थिति ज्यादा गंभीर है। अगर किसानों को समय से उर्वरक नहीं मिले, तो असर पहली फसल के साथ ही नजर आने लगेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उत्पादन 50: तक कम हो सकता है और इसका परिणाम युद्ध से ज्यादा भयावह हो सकता है।

PM Modi inaugurates

INDIA AI IMPACT EXPO



प्रधानमंत्री ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का किया उद्घाटन
भारत एआई में अवसर और भविष्य की रूपरेखा देखता है-पीएम

—:पेज 23 :—

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

RNI No.DELHIIN/2011/41355

DAVP No.0813F27125-025

संपादक

नासिर खान

सलाहकार संपादक

राकेश त्रिपाठी

डॉ. ईशा

अर्चना ज्योती

राजनीतिक संपादक

इंजी.ए पी सिंह

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)

प्रशांत दत्त मिश्रा

कानूनी सलाहकार

डी.बी.गोस्वामी,सलीम खान

(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

चीफ बिजनेस एंजीन्यूटिव

समीर अख्तर

वर्ष-15,अंक:172,मार्च 2026

मूल्य ₹ 20

विदेश प्रतिनिधि

विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख

सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख

अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

श्वेतांक वर्मा

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

संजय सिन्हा

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

सुनील नेगी

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख

शाहिद अस्करी

दक्षिणांचल ब्यूरो प्रमुख

इमरान खान

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख

योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख

शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख

साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

रानू पाठक

पश्चिम बंगाल,दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी

नरेश कुमार श्रीवास्तव

विशेष संवाददाता

गुफरान खान

प्रमुख संवाददाता

गुलशन अरोड़ा



राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर सरकार पर लगाए आरोप...24



भारत सेमीफाइनल की रेस में बरकरार.....49

यह युद्ध, तेल का खेल तो नहीं?.....13

केंद्रीय बजट में राजकोषीय संयम पर दिया गया विशेष बल..... 22

पीएसयू की खबरें.....29

अजित पवार विमान हादसा : भतीजे ने लगाया साजिश का आरोप.....36

हरिद्वार में भव्य कुंभ मेले की तैयारी...42

48 घंटों में हो रही मौतों से हरियाणा गांव में छाया मातम.....46

गढ़वाली फिल्म धंगतोल सिनेमाघरों में रिलीज हुई.....50

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो

मोहम्मद आसिफ (वरिष्ठ संवाददाता)

मथुरा ब्यूरो

विनय चौधरी (संवाददाता)

कानपुर ब्यूरो

अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)

बलिया ब्यूरो

डॉ.कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता),

आरा ब्यूरो

विमलेश कुमार (संवाददाता)

हाजीपुर ब्यूरो

राहुल कुमार (संवाददाता)

कार्यालय

कॉरपोरेट ऑफिस

91, फर्स्ट फ्लोर जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर,

दिल्ली- 110092

संपादकीय कार्यालय

आर-141/3 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092

मोबाइल-9718647540 Ph.011-46536014

ईमेल-primespectator@gmail.com, primeindia-mediahouse@gmail.com

वेबसाइट-primeindiamediahouse.com

primecrimeindia.com & netaindia.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा ANEJA PRINTERS, C-11, SECTOR-10, NOIDA (UP) से मुद्रित तथा आर-141/3 रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित।

सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टोर के किसी भी रचना के प्रकाशन से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखक के निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

ईरान, इजरायल-अमेरिका युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ते कदम

ईरान में 1300 से अधिक मौतें, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत



नासिर खान
वरिष्ठ पत्रकार

28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध एक पूर्ण सैन्य टकराव में बदल चुका है जिसे इजरायल ने शॉपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने शॉपरेशन एपिक पयुरी नाम दिया है। युद्ध के पहले ही दिन (28 फरवरी), इजरायल और अमेरिका ने तेहरान में एक उच्च स्तरीय बैठक पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई और कई शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए हैं। अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत प्ले क्मद को टॉरपीडो से डुबो दिया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोने की पहली बड़ी घटना है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों (जैसे नतांज और फोर्डो) और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड्स पर 3,000 से अधिक हवाई हमले किए हैं। युद्ध में ईरान में 1300 से अधिक मौतें हुईं सर्वोच्च नेतृत्व का खात्मा, नौसेना का भारी विनाश हुआ। वहीं इजरायल 12 नागरिकों की मौत, 1400 से अधिक लोग घायल, शहरों में बुनियादी ढाँचे को नुकसान हुआ। अमेरिका 6 सैन्य कर्मियों की मौत, रियाद और दुबई में दतावासों के पास

ड्रोन हमले।

ईरान की जवाबी कार्रवाई

ईरान ने हार मानने के बजाय रसवाइवल मोडर् में कड़ा पलटवार किया। ईरान ने खाड़ी देशों (यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत) में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। तेहरान और अन्य क्षेत्रों से इजरायल के तेल अवीव और यरुशलम जैसे शहरों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य की बंदी ईरान ने Strait of Hormuz को बंद करने की घोषणा की है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति ठप होने का खतरा पैदा हो गया है।

भारत पर प्रभाव और वैश्विक स्थिति

तेहरान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को घरों के अंदर रहने और अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेल की कीमतें रु युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें +120 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया रूस और चीन ने इस हमले की निंदा की है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। यह युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर है। जहाँ अमेरिका

और इजरायल का लक्ष्य तख्तापलट (Regime Change) है, वहीं ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ मध्य पूर्व के अन्य देशों को भी इस आग में खींच रहा है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यह वीडियो पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण हवाई हमलों और जमीनी सैन्य ऑपरेशनों की ताजा जानकारी और विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करता है।

सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत

ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर सोशल पर खामेनेई की मौत की बात कही थी। अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया था जिसके बाद खामेनेई की मौत की खबर आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था, खामेनेई का तेहरान स्थित आवास एक जबरदस्त और अचानक हुए हमले में तबाह हो गया है, और ऐसे कई संकेत हैं कि 86 साल के मौलवी अब नहीं रहे। ईरान ने इस हमले का जवाब इजरायल और चार खाड़ी अरब देशों, जहां अमेरिका के मिलिट्री



बेस हैं— बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की ओर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करके दिया है। सरकारी टीवी चैनलों पर प्रेजेंटर्स के पढ़े गए बयानों से ये पता चला है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की शनिवार तड़के उनके दफ्तर में मौत हुई, जब वह अपने कामकाज में व्यस्त थे। तेहरान में खामेनेई के दफ्तर लीडरशिप हाउस कंपाउंड के कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुँचा है। ईरान की इस्लामिक रिवाल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से जुड़ी तसनीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खामेनेई की अपने दफ्तर में हुई मौत इस बात का सबूत है कि उनके कहीं छिप जाने की खबरें धुश्मनों का मनोवैज्ञानिक युद्ध थीं।

ईरान में क्या हो रहा है?

28 फरवरी को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 09:30 बजे के कुछ देर बाद, ईरानी मीडिया ने राजधानी तेहरान में धमाकों की खबर दी। तस्वीरों में शहर के जम्हूरी स्क्वायर और हसन अबाद स्क्वायर के ऊपर धुआँ दिखाई दिया। खबरों के मुताबिक कि देश के कई दूसरे शहरों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसमें तेहरान के पास करज, देश के बीच में इस्फहान और कोम, और पश्चिम में करमानशाह शामिल हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में लोग धमाकों वाली जगहों के पास घबराकर भागते हुए दिख रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में चीखने और रोने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। तेहरान में लीडरशिप हाउस के एक किलोमीटर के अंदर धमाके दिखे, जो ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का आवासीय परिसर है। कंपाउंड में काफी नुकसान के निशान दिखे, जिसमें काली पड़ी इमारतें, मलबा और धुएँ का गुबार शामिल है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि हमले के समय खामेनेई वहाँ थे या नहीं। 28 फरवरी की दोपहर को जब सुप्रीम लीडर की सेहत के बारे में पूछा गया, तो

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने बताया कि वह कुछ भी कन्फर्म करने की हालत में नहीं हैं। लेकिन 28 फरवरी की शाम को इजराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि हमने तेहरान के बीचों-बीच तानाशाह खामेनेई के कंपाउंड को तबाह कर दिया। इस बात के कई संकेत हैं कि तानाशाह खुद अब नहीं रहे। इसके बाद ट्रंप ने ट्विथ सोशल पर लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई की मौत हो चुकी है।

ट्रंप ने लिखा कि इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए, वह हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। वह या उसके साथ मारे गए दूसरे लीडर कुछ भी नहीं कर सके। यह ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस पाने का सबसे बड़ा मौका है।

तेहरान में हमले

खबरों के मुताबिक, राजधानी में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान के ऑफिस को भी पहले हमलों में निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि राष्ट्रपति पेजेशिकयान सुरक्षित हैं और बाद में उन्होंने एक बयान जारी किया। 28 फरवरी की सुबह मॉनिटर्स को लगभग पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकाउट का पता लगा, इसके बावजूद पूरे दिन हमलों और धमाकों की कई और घटनाएँ हुईं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी, इरना ने कहा कि तेहरान, कराक और कोम के साथ-साथ पश्चिमी प्रांतों लोरेस्तान, हमादान, करमानशाह और इलमय उत्तर पश्चिम में तबरीज और दक्षिणी खाड़ी प्रांत होर्मोजगन के कुछ हिस्सों, जिसमें केशम द्वीप भी शामिल है, में धमाके हुए। पश्चिमी शहर देजफुल दक्षिण में शिराज और केरमान के बाहरी इलाकों उत्तर-पश्चिम में कुर्दिस्तान और पश्चिमी अजरबैजान मध्य प्रांत मरकाजीय उत्तर में कजिवन और जांजन, और दक्षिण-पूर्व में सिस्तान बलूचिस्तान में भी धमाकों की खबरें थीं। 28 फरवरी की शाम को, ईरानी रेड क्रिसेंट

के एक प्रवक्ता ने स्थानी मीडिया को बताया कि ईरान के 31 में से 24 प्रांत अमेरिकी और इसराइली हमलों में निशाना बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देर शाम 20:45 तक देश भर में कुल 201 लोग मारे गए और 747 अन्य घायल हुए, लेकिन इलाके का ब्योरा नहीं दिया। सरकारी मीडिया ने कहा कि होर्मोजगन प्रांत के मिनाब में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 85 लोग मारे गए। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने कहा है कि देश का एयरस्पेस अगली सूचना तक बंद है।

अमेरिका और इजरायल ने क्या कहा है?

28 फरवरी सुबह पहला बयान इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काटज का आया। उन्होंने कहा कि उनके देश ने खतरों को दूर करने के लिए ईरान पर हमला किया है और इजरायलियों को जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। इसके करीब एक घंटे बाद ट्रंप ने ट्विथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हमलों में अमेरिका के शामिल होने की पुष्टि की गई और कहा गया कि इसका मकसद ईरानी शासन से मिल रहे खतरों को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना था। उन्होंने आगे कहा कि हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिला देंगे। इसे फिर से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हम उनकी नेवी को खत्म कर देंगे। हम यह पक्का करेंगे कि इलाके के आतंकवादी प्रॉक्सी अब इलाके या दुनिया को अस्थिर न कर सकें और हमारी सेना पर हमला न कर सकें। ट्रंप ने कहा कि और हम यह पक्का करेंगे कि ईरान को परमाणु हथियार न मिले। इससे पहले ट्रंप ने कई हफ्तों तक ईरान को धमकियाँ दीं और कहा था कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर नई डील पर सहमत नहीं होता है तो वह मिलिट्री एक्शन का आदेश देंगे। ईरान ने बार-बार कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वह परमाणु हथियार हासिल करना नहीं चाहता है। ट्रंप ने ईरानी सेना के सदस्यों से यह भी कहा कि वे या तो अपने हथियार डाल दें और उन्हें भूरी छूट मिले, या पक्की मौत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ईरानी नागरिकों से भी अपने घरों में रहने और मौलवी वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहने को कहा। ट्रंप ने कहा कि जब हमारा काम खत्म हो जाए, तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लें। यह आपको ही लेना होगा। यह शायद कई पीढ़ियों के लिए आपका एकमात्र मौका होगा। इजराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान में आतंकवादी शासन से पैदा हुए अपने अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए ऑपरेशन किया है। ट्रंप को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने अपना संदेश दोहराया कि ईरान को ऐसे परमाणु

हथियारों से लैस नहीं होने देना चाहिए जो उसे पूरी ईसानियत के लिए खतरा बनने में उसकी मदद करे। उन्होंने कहा कि ये हमले बहादुर ईरानी लोगों के लिए अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने का अवसर बनाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में सभी तबकों के लोगों के लिए जुल्म से आजाद होने और एक आजाद और शांति चाहने वाला ईरान बनाने का समय आ गया है। अमेरिकी मिलिट्री के सेंट्रल कमांड ने 28 फरवरी शाम को एक बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइली सेनाओं ने ईरानी सरकार के सिक्वोरिटी सिस्टम को खत्म करने के लिए, फौरन खतरा बनने वाली जगहों को प्राथमिकता देते हुए टारगेट पर हमला करना शुरू कर दिया है। कमांड ने कहा कि खबर है कि इन टारगेट्स में इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर (आईआरजीसी) कमांड-एंड-कंट्रोल फैसिलिटी, एयर डिफेंस क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट और मिलिट्री एयरफील्ड शामिल थे। इस बीच इजरायल डिफेंस फोर्स ने घोषणा की कि लगभग 200 फाइटर जेट ने पश्चिमी और मध्य ईरान में मिसाइल ऐरे और डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बड़े हमले में हिस्सा लिया था। इसमें आगे कहा गया कि लड़ाकू विमानों ने एक साथ लगभग पांच सौ टारगेट पर सैकड़ों हथियार गिराए, जिनमें एरियल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर शामिल थे, और ईरान की हमला करने की क्षमता को बहुत कम कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इन हमलों ने आयतुल्लाह शासन के बड़े अधिकारियों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े लोगों को बेअसर कर दिया। आईडीएफ ने ईरान के डिफेंस सिस्टम के सात बड़े सदस्यों के नाम बताए, जिनके मारे जाने की बात कही गई है। इनमें ईरान की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और खामेनेई के भरोसेमंद सलाहकार अली शमखानी, साथ ही आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादेह शामिल हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि पिछले जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद से इसराइली और अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने शनिवार के हमलों के लिए एक षाहरी और पूरी जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस शुरू की थी। इस दौरान अमेरिका ने ईरान की तीन खास न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए थे।

ईरान ने क्या जवाब दिया है?

ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल और अमेरिका पर झूरी तरह से बिना उकसावे के, गैरकानूनी और नाजायज़ जंग शुरू करने का आरोप लगाया। ईरानी विदेशी मंत्री अरागची ने एक्स पर लिखा, ष्मारी ताकतवर सेना इस दिन के लिए तैयार है और हमलावरों को वह सबक सिखाएगी जिसके वे हकदार हैं। ईरानी रक्षा



मंत्रालय ने भी इजरायल और अमेरिका के क्रूर हमले का कठोर और दोनों देशों में अफसोस पैदा करने वाला जवाब देने की कसम खाई। ईरान के सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के हवाले से कहा कि उसकी सेना ने इजरायल में कई जगहों के साथ-साथ इस इलाके में अमेरिका की पांच बड़ी मिलिट्री जगहों, कतर में अल उदैद एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और जॉर्डन में मुवफफाक साल्टी एयरबेस पर हमला करके इन हमलों का जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरजीसी ने यह भी कहा कि अमेरिका के एक कॉम्बैट सपोर्ट वेसल पर मिसाइलों से गंभीर हमले हुए हैं, और कतर में अमेरिका का पीएफ-132 रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस बीच, इस इलाके में यूरोपियन यूनियन के नेवल मिशन, यूनावफोर एस्पाइड्स ने कहा कि आईआरजीसी ने वेसल को रेडियो मैसज भेजकर चेतावनी दी है कि खाड़ी में किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं है, जिससे दुनिया भर के तेल और गैस शिपमेंट का लगभग 20% गुजरता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने शनिवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन के सैकड़ों हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी अमेरिकी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है और इस इलाके में अमेरिकी इंस्टॉलेशन को कम से कम नुकसान हुआ है और इससे ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं इसराइली मीडिया ने बताया कि ईरान ने इजरायल की ओर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से ज्यादातर छोटी थीं, साथ ही दर्जनों अटैक ड्रोन भी दागे। उन्होंने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोक लिया, जबकि कुछ खुली जगहों पर गिरीं। मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि उसने सेंट्रल इजरायल में छर्रे लगने से घायल एक किशोर का इलाज

किया, और उत्तर में एक आदमी ब्लास्ट शॉकवेव से घायल हो गया। उसने आगे कहा कि उत्तर में एक दूसरा व्यक्ति मिसाइल के धमाके के बाद ऊंची जगह से गिरने से घायल हो गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े एक खुले हमले का सामना किया और उनमें से कई को रोक लिया। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि अबू धाबी शहर में गिरते मलबे से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। दुबई में लैंडमार्क पाम डेवलपमेंट में चार अन्य लोग घायल भी हो गए। दुबई एयरपोर्ट्स ने एक बयान में कहा कि शनिवार शाम को एक घटना में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल ट्रेफिक एयरपोर्ट है, उसका एक कॉन्कोर्स डैमेज हो गया और चार स्टाफ घायल हो गए। उसने बताया कि ज्यादातर टर्मिनल पहले ही पैसेंजर से खाली करा लिए गए थे। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अली अल सलेम एयरबेस, जहां अमेरिकी रहते हैं, उसे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिससे तीन कुवैती सैनिक छर्रे लगने से घायल हो गए। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन ने हमला किया, जिससे मामूली चोटें आईं और कुछ सामान का नुकसान हुआ। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि मनामा और मुहरक में तीन रिहायशी इमारतों को ड्रोन हमलों और एक इंटरसेप्टेड मिसाइल के गिरे मलबे से नुकसान हुआ। बहरीन सरकार ने यह भी बताया कि अमेरिकी नेवी के फिफ्थ फ्लीट के सर्विस सेंटर पर मिसाइल हमला हुआ। कतर ने कहा कि उसकी सेना ने देश की ओर दागी गई कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं।

क्या इस इलाके में सफर करना सुरक्षित है?

बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने इस इलाके में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मिडिल ईस्ट जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स को डायवर्ट या

कैसिल कर दिया है। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को इस इलाके में लैंड करने वाली करीब 4,218 फ्लाइट्स में से 966 कैसिल कर दी गईं। इसमें कहा गया है कि रविवार की 4,329 शेड्यूल फ्लाइट्स में से 716 फ्लाइट्स पहले ही कैसिल हो चुकी हैं। विज एयर ने 7 मार्च तक इजरायल, यूएई में दुबई और अबू धाबी, जॉर्डन में अम्मान और सऊदी अरब में मंगलवार तक फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने बुधवार तक तेल अवीव और बहरीन की फ्लाइट्स कैसिल कर दी हैं। कंपनी ने कहा कि अगर आप लंदन हीथ्रो और अबू धाबी, अम्मान, बहरीन, दोहा, दुबई या तेल अवीव के बीच फ्लाइट लेने वाले हैं, तो आप 6 मार्च तक अपनी फ्लाइट बिना कोई शुल्क दिए बदल सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, 4 मार्च तक ट्रैवल करने वाले कस्टमर पूरे रिफंड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्विस् इंटरनेशनल एयरलाइन्स ने एक बयान में कहा, फ्रैंक्स और लुफ्थांसा ग्रुप एयरलाइन्स ने 7 मार्च तक तेल अवीव, बेरुत (लेबनान में), अम्मान, एरबिल (इराक में) और तेहरान के लिए उड़ानें रोक दीं। सरकारी मीडिया के मुताबिक, कुवैत की एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि वह अगली सूचना तक ईरान के लिए सभी उड़ानें रोक रही है। एमिरेट्स ने दुबई से आने-जाने के लिए अपने ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिए हैं। लुफ्थांसा, एयर इंडिया, वर्जिन अटलांटिक और टर्किश एयरलाइन्स ने भी उड़ानें कैसिल करने की घोषणा की है। इस इलाके के कुछ देशों, जिनमें इराक और जॉर्डन शामिल हैं, उन्होंने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। सरकारी मीडिया ने बताया कि यूएई ने कहा कि उसने एहतियात के तौर पर अपना एयरस्पेस फ्लूट हद तक और कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। इस बीच, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, यमन, तुर्की, सऊदी अरब और ओमान के लिए ब्रिटेन फॉरेन ऑफिस की ट्रैवल गाइडलाइन्स अब यात्रियों को फसतर्क रहने, स्थानीय अधिकारियों की सलाह मानने और अगर कहा जाए तो सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने की सलाह दे रही हैं।

खामेनेई के अलावा और कौन-कौन मारे गए

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरानी सेना का शीर्ष नेतृत्व भी मारा गया है। ईरानी टेलीविजन की रिपोर्ट में कहा गया है देश के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुलरहीम मौसवी हवाई हमलों में मारे गए। ईरान ने यह भी पुष्टि की है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपो की भी हमले में मौत हो गई है। रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिरजादेह भी मारे गए हैं। सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन अली शमखानी की भी मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने



यह भी बताया है कि खामेनेई की बेटी, दामाद और पोते या पोती की भी इस हमले में मौत हो गई। एक खुफिया स्रोत और एक सैन्य स्रोत ने सीबीएस न्यूज को बताया है कि इन हमलों में कुल मिलाकर लगभग 40 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं।

आईआरजीसी की चेतावनी के बाद ट्रंप का बयान

दूसरी ओर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इजरायल पर हमला करेगा। इस बयान में कहा गया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म्ड फोर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी अड्डों की ओर शुरू होगा। इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पलटवार करेगा। उन्होंने दृढ़ सोशल पर लिखा, ईरान ने अभी कहा है कि वे आज बहुत जोरदार हमला करेंगे, इतना जोरदार जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन, बेहतर होगा कि वे ऐसा न करें, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम उन पर ऐसा जोरदार हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं सरकारी टीवी चैनलों पर प्रेजेंटर्स के पढ़े गए बयानों से ये पता चला है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की शनिवार तड़के उनके दफ्तर में मौत हुई, जब वह अपने कामकाज में व्यस्त थे। वहीं तेहरान में खामेनेई के दफ्तर लीडरशिप हाउस कंपाउंड के कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुँचा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से जुड़ी तसनीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खामेनेई की अपने दफ्तर में हुई मौत इस बात का सबूत है कि उनके कहीं छिप जाने की खबरें दुश्मनों का मनोवैज्ञानिक युद्ध थीं।

ट्रंप ने और क्या कहा?

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दृढ़ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, खामेनेई, जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे, अब मर चुके हैं। यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए ही न्याय नहीं है, बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है, जिन्हें खामेनेई और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला या घायल कर दिया। वह हमारी खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणालियों से बच नहीं सके, और इजरायल के साथ मिलकर किए गए अभियान में, न तो वे और न ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ कर सके। यह ईरान के लोगों के लिए अपने देश को वापस लेने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है। हमें सुनने में आ रहा है कि उनके कई आईआरजीसी, सैन्य अधिकारी और अन्य सुरक्षा व पुलिस बल अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे सुरक्षा (इम्युनिटी) मांग रहे हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था— अभी वे सुरक्षा पा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। इस्लामी है कि आईआरजीसी और पुलिस शांतिपूर्वक ईरान के देशभक्तों के साथ मिल जाएँगे और एक इकाई की तरह देश को उस महानता तक वापस ले जाएँगे, जिसके वह लायक है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ खामेनेई की मौत ही नहीं, बल्कि देश एक ही दिन में बहुत हद तक बर्बाद यहाँ तक कि लगभग मिट चुका है। हालाँकि, भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जितनी देर तक जरूरी हो, बिना रुके जारी रहेगी, ताकि हम पूरे मध्य पूर्व में और वास्तव में दुनिया में शांति के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। वहीं खामेनेई की मौत से जुड़े दावों के बाद ईरान के कराज शहर में कथित तौर पर लोगों को जश्न मनाते देखा गया है। एक सोशल मीडिया वीडियो, जिसे एक्स पर साझा किया गया और उसे बीबीसी फारसी ने सत्यापित भी किया है, उसमें कुछ इरानियों को कराज में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की रिपोर्ट के बाद जश्न मनाते देखा गया है। हालांकि यह सब डोनाल्ड



ट्रंप के एक्स पर पोस्ट करने से पहले हुआ था।

ईरान के स्कूल पर हुए हमले के बारे क्या लिख रहा है अमेरिकी और अरब मीडिया?

ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले में मारी गई लड़कियों और स्टाफ को मंगलवार को दफना दिया गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये लोग अमेरिका और इजरायल की ओर से हुए हमले में मारे गए थे। हालांकि अमेरिका ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और कहा है कि वो जांच करवा रहा है कि हमला किसने किया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को दक्षिणी ईरान के शहर मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें छात्राओं के अलावा स्कूल के स्टाफ के लोग भी शामिल थे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह स्कूल ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक नौसैनिक अड्डे के बिल्कुल पास स्थित है।

स्कूल के सामने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर का ठिकाना होने का जिन्न

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता के हवाले से लिखा है, श्शनागरिकों की सुरक्षा अमेरिका के लिए बेहद अहम है। अमेरिका अनजाने में होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरतता रहेगा। अखबार के मुताबिक मीनाब के स्कूल पर हुए इस बड़े हमले की खबर अमेरिका में भी चर्चा का विषय बन गई है। अखबार लिखता है कि पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप और उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन से दूरी बनाने वाली अमेरिका की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर इस हमले की आलोचना की। अखबार के मुताबिक उन्होंने लिखा, धैर्य इसके लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। मैंने इसके लिए पैसे दान नहीं किए। मैंने इसके लिए चुनावों या कांग्रेस में वोट नहीं दिया। यह दिल तोड़ देने वाली

और दुखद घटना है। और कितने निर्दोष लोग मरेंगे? हमारे अपने सैनिकों का क्या होगा? यह वह अमेरिका नहीं है जिसकी हमने कल्पना की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अन्य खबर में ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का हवाला दिया गया है। अखबार के मुताबिक इन अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे अभी भी यह जांच कर रहे हैं कि युद्ध के पहले दिन ईरान में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हुआ हमला क्या अमेरिकी हवाई हमले का नतीजा था। अखबार ने लिखा है कि यह अब भी साफ नहीं है कि स्कूल पर हमला क्यों हुआ या किस देश की सेना ने उस पर हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी कह चुके हैं, धैर्य सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम कभी भी नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाते, लेकिन हम इस मामले को देख रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक उसके एक वेरिफाइड वीडियो में स्कूल पर हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक भारी भीड़ सड़कों पर उतरी। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से वेरिफाइड वीडियो फुटेज के मुताबिक, स्कूल से लगभग पांच मील दूर एक कब्रिस्तान में मजदूरों ने एक साथ कई कब्रें खोदी थीं। यूनेस्को ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि स्कूल में स्टूडेंट्स की हत्याएं अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत स्कूलों को दी गई सुरक्षा का शंभर उल्लंघन है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने इस हमले के बारे में बुधवार को कहा, अमेरिका कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाता, जबकि ईरान का दुष्ट शासन ऐसा करता है। वह नागरिकों को निशाना बनाता है, बच्चों को मारता है और पिछले कुछ हफ्तों में अपने ही हजारों लोगों को मार चुका है।

कनाडाई मीडिया आउटलेट ने क्या

कहा वहीं कनाडा के न्यूज आउटलेट सीबीसी न्यूज ने लिखा है कि उनकी एक विजुअल जांच में नई सैटेलाइट तस्वीरों और सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर संकेत मिलता है कि स्कूल पर हुई बमबारी दरअसल उस इमारत

के बिल्कुल पास मौजूद एक सैन्य परिसर पर किए गए सटीक हवाई हमले का नतीजा था। सीबीसी के मुताबिक हमले के तुरंत बाद कई वीडियो सामने आए जिनमें मीनाब शहर का एक लड़कियों का स्कूल लगभग पूरी तरह तबाह दिखाई दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह सीबीसी ने लिखा है कि यह स्कूल पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक ठिकाने का हिस्सा था। सीबीसी ने लिखा है कि बमबारी के तुरंत बाद सोशल मीडिया और आधिकारिक स्रोतों से अलग-अलग दावे सामने आने लगे कि स्कूल पर हमला किसने किया और क्या यह जानबूझकर किया गया था। सीबीसी ने लिखा है कि उसकी विजुअल जांच टीम ने घटनास्थल के कई वीडियो की जांच और पुष्टि की। इनमें कई अलग-अलग धुएं के गुबार दिखाई देते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उस इलाके पर एक से अधिक बार हमला हुआ। बुधवार को जारी प्लेनेट लैब्स के सैटेलाइट चित्रों ने भी इसकी पुष्टि की, जिनमें परिसर के भीतर कई गड्ढे दिखाई दिए। सीबीसी के मुताबिक टोरंटो स्थित ईरानी फैक्ट-चेकिंग ग्रुप फ़ैक्टनेमेह के मिलिट्री रिसर्चर यूसुफ रियाजी ने कहा, प्यह रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया सटीक हमला था। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक हमलों का पैटर्न सटीक टारगेटेड हथियारों का लगता है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने सीबीसी को बताया कि स्कूल का निशाना बन जाना या तो हथियार प्रणाली की गलती हो सकती है या फिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की खुफिया जानकारी जुटाने में बड़ी चूक। अब तक न तो इजरायल की सेना और न ही अमेरिकी सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

बच्चों की जानबूझकर हत्या की गई :

अल-जजीरा

ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने स्कूल पर हमले का जिक्र करते हुए लिखा है, श्शसोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, कथित तौर पर हमले के तुरंत बाद का दृश्य दिख रहा है। जली हुई दीवारों से उठता धुआं दिख रहा है और सड़क पर मलबा बिखरा पड़ा है। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हैं। अखबार लिखता है कि वो बम विस्फोट की रिपोर्ट, मृतकों की संख्या और वीडियो के स्रोत की तुरंत स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। फैक्टचेक संगठन फैक्टनेमेह ने स्कूल परिसर की अन्य तस्वीरों के साथ वीडियो का मिलान किया और निष्कर्ष निकाला कि वीडियो प्रामाणिक है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी फुटेज की पुष्टि की है और बताया है कि यह स्कूल का ही है। श्शगार्डियन ने लिखा है कि यह स्कूल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बैरक में स्थित लग रहा है। दूसरी ओर कतर के न्यूज आउटलेट अल जजीरा की अरबी सेवा के मुताबिक अमेरिका ने मीनाब की स्कूली छात्राओं

की जानबूझकर हत्या की है। अल जजीरा ने लिखा कि सोशल मीडिया पर इस तबाही की तस्वीरें फैलते ही इजरायल और अमेरिका के अधिकारियों ने इस हमले से खुद को अलग बताने की कोशिश की। अल जजीरा ने लिखा कि कुछ इजरायल समर्थित वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया कि यह जगह ध्वस्तामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बेस का हिस्सा थी। लेकिन अल जजीरा की डिजिटल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक दशक से अधिक समय के सैटेलाइट चित्रों, हाल के वीडियो, समाचार रिपोर्टों और ईरानी सरकारी बयानों के विश्लेषण से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। जांच के निष्कर्ष बताते हैं कि कम से कम पिछले दस वर्षों से यह स्कूल पास के सैन्य ठिकाने से स्पष्ट रूप से अलग था। जांच यह भी संकेत देती है कि हमले के पैटर्न से उस खुफिया जानकारी की सटीकता पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिसके आधार पर बमबारी की गई। अल जजीरा ने आगे लिखा कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सुबह 10:23 बजे तक स्कूल की इमारत पूरी तरह सुरक्षित थी। ईरानी सूत्रों के अनुसार सुबह 10:45 बजे एक गाइडेड मिसाइल ने सीधे स्कूल को निशाना बनाया। अल जजीरा की जांच टीम ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए दो वीडियो का विश्लेषण किया और उन्हें सैटेलाइट चित्रों से मिलाकर उनकी सटीक लोकेशन निर्धारित की। अल जजीरा ने लिखा कि पहले वीडियो में सैन्यदल अल-शुहदा सैन्य परिसर के भीतर से उठता हुआ दिखाई देता है, जिससे पुष्टि होती है कि सैन्य बेस भी निशाने पर था। लेकिन दूसरे वीडियो में दो अलग-अलग जगहों से उठता काला धुआँ साफ दिखाई देता है। एक सैन्य बेस के भीतर से और दूसरा लड़कियों के स्कूल के स्थान से। दोनों के बीच की दूरी सैटेलाइट चित्रों में दिखाई गई दूरी से मेल खाती है। इससे यह दावा कमजोर पड़ता है कि स्कूल को नुकसान पास के सैन्य ठिकाने से उड़े मलबे या छरों से हुआ। इसके बजाय यह संकेत मिलता है कि स्कूल पर अलग से सीधे हमला हुआ था। अल अरबिया ने उस खबर का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि ईरान में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर रही संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच समिति ने बुधवार को तेहरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों की निंदा की है। अल अरबिया ने संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ऑन ईरान के हवाले से लिखा है, श्रेय हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के खिलाफ हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाता है। तुर्की के सरकारी मीडिया आउटलेट टीआरटी वर्ल्ड ने भी स्कूल पर हमले के बाद व्हाइट हाउस के उस बयान का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें अमेरिका की भूमिका नहीं है। टीआरटी



वर्ल्ड ने लिखा है, बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब यह पूछा गया कि शनिवार को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के शुरुआती हमलों में से किसी एक के कारण स्कूल के बच्चों की मौत हुई थी या नहीं, तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका नागरिकों को निशाना नहीं बनाता।

ईरान-इजराइल युद्ध बढ़ते संकट का दिन-प्रतिदिन का विस्तृत विवरण

संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने शनिवार (28 फरवरी, 2026) को ईरान पर हमला किया, जिससे पश्चिम एशिया एक नए संघर्ष में डूब गया, जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सुरक्षा खतरा समाप्त हो जाएगा और ईरानियों को अपने शासकों को उखाड़ फेंकने का मौका मिलेगा। इन हमलों से आसपास के तेल उत्पादक खाड़ी अरब देशों में तनाव बढ़ गया क्योंकि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गईं, और इजरायल ने कहा कि तेहरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागकर जवाब दिया। ईरान ने जवाबी हमले करते हुए इजरायल पर पलटवार किया और प्रतिशोध की चेतावनी दी। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने शनिवार (28 फरवरी, 2026) को कहा कि इजरायल और अमेरिका को अपने कार्यों पर पछतावा होगा।

दिन 1 इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से तेहरान पर हमला किया और इसे पूर्व-emptive कार्रवाई बताया। ऑपरेशन रोसिंग लायन या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाने जाने वाले इस अभियान में तेहरान, कोम और इस्फहान सहित कई प्रमुख ईरानी शहरों पर हमला किया गया इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ-साथ 200 से अधिक नागरिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और यरुशलम के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार की। बहरीन में अमेरिकी फिफथ फ्लीट बेस, कतर में अल उदैद एयर बेस, कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा एयर बेस ईरान के

निशाने पर थे। दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों, जिनमें बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड्स शामिल हैं, पर भी हमले होने की खबर है।

दिन 2 ईरान पर संयुक्त अमेरिकी-इजरायली आक्रमण जारी रखते हुए, अमेरिकी सेना ने रविवार (1 मार्च, 2026) को घोषणा की कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुख्यालय को नष्ट कर दिया है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। इसी बीच, ईरान ने इजरायली शहर बेत शेमेश पर मिसाइल हमला किया, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद बचाव दल के अनुसार कम से कम नौ लोग मारे गए और 28 अन्य घायल हो गए। ईरानी समाचार एजेंसी आईएसएनए ने बताया कि उत्तरी तेहरान स्थित गांधी अस्पताल को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में निशाना बनाया गया था। खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों के जवाब में, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यदि आवश्यक हो तो वे ईरान के खिलाफ प्रक्षामक कार्रवाई करके अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ईरान में, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद सरकार ने अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद का नेतृत्व करने के लिए नामित किया।

दिन 3 संघर्ष के लगातार तीसरे दिन, लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा सोमवार (2 मार्च, 2026) की सुबह सीमा पार मिसाइलें दागने के बाद इजराइल ने बेरुत पर हमलों की बौछार कर दी। एक ऐसे घटनाक्रम में जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लगभग पांचवें हिस्से को खतरे में डाल सकता है और कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा सकता है, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया है और चेतावनी दी है कि ईरान वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को आग लगा देगा। खाड़ी क्षेत्र में, कुवैत ने घोषणा की कि उसने ईरान द्वारा पड़ोसी राज्यों को निशाना बनाकर किए गए जवाबी हमलों के तहत शत्रुतापूर्ण ड्रोन को रोका है। ये हमले अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में किए गए थे।

ईरान ने यह भी कहा कि उसने पूर्वी यरुशलम में हमले के अलावा तेल अवीव में एक इजरायली सरकारी परिसर के साथ-साथ हाइफा में सुरक्षा और सैन्य सुविधाओं पर मिसाइल हमले किए हैं।

दिन 4 पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते संघर्ष के बीच, ईरानी रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार, 27 फरवरी, 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा हमले शुरू किए जाने के बाद से ईरान में 780 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल की सेना ने बुधवार (4 मार्च, 2026) को कहा कि उसने ईरान के अंदर लक्ष्यों पर पबड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं, इस्लामिक गणराज्य द्वारा इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइलों की तीन अलग-अलग बौछारें दागने के कुछ घंटों बाद। इस बीच, मंगलवार रात (3 मार्च, 2026) को इराक के एरबिल और संयुक्त अरब अमीरात के दोहा, दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। दुबई के अधिकारियों ने कहा कि ये धमाके हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा किए गए श्लोकथाम अभियानों का परिणाम थे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर दो ड्रोन से किए गए हमले के कारण पसीमित आग लगी, इससे पहले कुवैत में अमेरिकी दूतावास में भी एक घटना हुई थी, जिसके बाद कुवैत ने घोषणा की कि वह अगले आदेश तक बंद रहेगा।

दिन 5 अमेरिकी-इजरायली बमबारी जारी रहने के बावजूद, ईरान अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी की सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्ति में तेजी लाने की प्कोशिश कर रहा है, राज्य टेलीविजन ने बुधवार (4 मार्च, 2026) को रिपोर्ट किया। इस बीच, इजरायल के रक्षा मंत्री, इजरायल काटज ने चेतावनी दी कि इजरायल, अयातुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए किसी भी ईरानी नेता को निशाना बनाएगा और उसकी हत्या कर देगा। संघर्ष के पांचवें दिन में प्रवेश करते ही, इजराइल ने ईरान और लेबनान पर नए हमले किए। लेबनानी सरकारी मीडिया ने बताया कि नवीनतम बमबारी में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान में, इजराइली सेना ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने जमीनी अभियान के तहत खियाम शहर में दाखिल हुई। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान के पास मिसाइल प्रक्षेपण करने की पर्याप्त क्षमता बनी हुई है, जबकि इजरायल लगातार इस्लामी गणराज्य में प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बना रहा है। अलग से, दिवंगत सर्वोच्च नेता के एक वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद मुखबर ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है और वह प्जब तक चाहे युद्ध जारी रखने में सक्षम है। इसी बीच, बुधवार को श्रीलंका के तट से दूर हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत पर हमला

किया, जो डूब गया। इस हमले से पश्चिम एशियाई संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के ओर करीब आ गया है। इस हमले में कम से कम 83 लोग मारे गए। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले की पुष्टि की। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाने वाला सार्वजनिक समारोह, जो मूल रूप से तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना कक्ष में होने वाला था, स्थगित कर दिया गया है, राज्य मीडिया ने यह जानकारी दी।

दिन 6

अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा एक ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने और तेहरान की इस चेतावनी के बाद कि वह पूरे क्षेत्र में सैन्य और आर्थिक संपत्तियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, पश्चिम एशिया में हवाई हमले गुरुवार (5 मार्च, 2026) को अपने छठे दिन में प्रवेश कर गए। गुरुवार (5 मार्च, 2026) की सुबह ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं। इजराइल ने लेबनान में नए अभियानों की घोषणा के तुरंत बाद ईरानी हमले की पुष्टि की, जिसमें बेरुत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी बीच, एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा एक अन्य ईरानी क्रिगेट को नष्ट करने और कम से कम 87 नाविकों को मारने के ठीक एक दिन बाद, गुरुवार को एक दूसरा ईरानी युद्धपोत श्रीलंका के क्षेत्रीय जलक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस जहाज में 100 से अधिक चालक दल के सदस्य सवार हैं, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि इसका भी वही हश्र हो सकता है जो इसके साथी जहाज का हुआ था, जो बुधवार को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर डूब गया था। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पूर्व अमेरिकी सेना के कर्नल डगलस मैकग्रेगर के इस दावे को खारिज कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघवी ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी संभावित जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, और आगाह किया कि इस तरह की वृद्धि ईरान के विरोधियों पर

विनाश लाएगी। इसी बीच, इजराइल के सैन्य प्रमुख ने घोषणा की कि उन्होंने इजराइली सेना को दक्षिणी लेबनान में इजराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्र का विस्तार करने का निर्देश दिया है। यह विस्तार उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के चल रहे अभियानों को और तेज करने का संकेत है। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि अधिकारियों ने देश के तट पर स्थित एक जहाज से ईरानी चालक दल के सदस्यों को उतारना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, "जहाज पर कुल 208 चालक दल के सदस्य हैं, और श्रीलंका ने ईरानी चालक दल को उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालक दल के सदस्यों के सुरक्षित रूप से उतर जाने के बाद, जहाज को त्रिकोमाली बंदरगाह पर ले जाया जाएगा।"

दिन 7

पश्चिम एशिया में गहराते संकट के लगातार सातवें दिन, इजरायली हवाई हमलों ने ईरान और लेबनान की राजधानियों को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने कथित तौर पर समुद्र में एक ईरानी ड्रोन वाहक पर हमला किया, जिससे इस्लामिक गणराज्य के युद्धपोतों के बेड़े को निशाना बनाने का उसका अभियान तेज हो गया। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने मध्य पूर्व में उत्पन्न हो रही स्थिति को एक प्रमुख मानवीय आपातकाल घोषित किया है, और समन्वित प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHCR) ने मध्य पूर्व में बढ़ते संकट को एक बड़ा मानवीय आपातकाल घोषित किया है, जिसके लिए पूरे क्षेत्र में तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, एजेंसी की आपातकालीन प्रमुख और अंतर-क्षेत्रीय शरणार्थी समन्वयक अयाकी इतो ने जिनेवा में पत्रकारों को बताया। इसी बीच, ईरान ने अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों पर नए सिरों से जवाबी हमले शुरू किए। श्रीलंका के तट पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत को टॉरपीडो से डुबोए जाने के दो दिन बाद, ईरान ने शुक्रवार (6 मार्च, 2026) को चेतावनी दी कि निहत्थे जहाज पर इस तरह के हमले को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता। इस बीच, भारत ने अमेरिकी अभियान में सहायता करने के दावों को खारिज कर दिया, और एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने इन रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया।



यह युद्ध, तेल का खेल तो नहीं?



विकास पारिक
विदेश प्रतिनिधि, लंदन

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया। अली खामेनेई मारे गए। दुनिया के अखबारों ने इसे परमाणु खतरे का अंत बताया, पश्चिमी नेताओं ने लोकतंत्र की जीत का नाटक किया, और टेलीविजन पर विशेषज्ञ बोलते रहे कि यह युद्ध मानवता के लिए है। लेकिन असली सवाल वो है जो कोई नहीं पूछता। होर्मुज जलडमरूमध्य एक संकरी समुद्री गली, केवल 21 मील चौड़ी उसके बारे में क्या? वही जलमार्ग जिससे हर रोज़ दो करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का तीस प्रतिशत। दुनिया की पाँचवीं हिस्सा प्राकृतिक गैस। यह नहर बंद हो गई है। और जो अमेरिका यह युद्ध लड़ रहा है, वही अमेरिका इस नहर को खुला रखने के लिए अपनी नौसेना तैनात कर

रहा है।

क्या यह संयोग है?

इतिहास बताता है कि अमेरिका जब भी मध्य-पूर्व में घुसा है, उसकी वजह लोकतंत्र नहीं, तेल रही है। 1953 में ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोसादेग को **CIA** ने हटाया था क्यों? क्योंकि उन्होंने ईरान का तेल राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश की थी। 1991 में कुवैत के लिए युद्ध वह खाड़ी के तेलक्षेत्रों की रक्षा थी। 2003 में इराक जिस देश में बाद में कोई सामूहिक विनाश के हथियार नहीं मिले, लेकिन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार मिला।

और अब ईरान। इस बार अंतर यह है कि ईरान के पास होर्मुज का भूगोल है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, उस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में पड़ता है। ईरान के पास यह शक्ति है कि वह उस नहर को तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन व्यावहारिक रूप से बंद कर सकता है। सस्ते ड्रोन से, बीमा कंपनियों को डराकर। डंमतो रुक गई। रूसवल्क्रे ने बवअमतंहम बंद किया। ठतमदज बतनकम +88 तक पहुँच गया। तेल के बाज़ार 1970 के बाद के

सबसे बड़े ऊर्जा संकट की बात करने लगे। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था। असली युद्ध यह नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों या न हों। असली युद्ध यह है कि दुनिया के ऊर्जा व्यापार की चाबी किसके हाथ में रहे। अमेरिका चाहता है कि होर्मुज उसके नियंत्रण में रहे या कम से कम किसी ऐसे देश के नियंत्रण में न रहे जो अमेरिकी हितों को चुनौती दे सके। ईरान वही चुनौती था।

अब भारत की बात करते हैं।

भारत की आधी से अधिक कच्चे तेल की ज़रूरत मध्य-पूर्व से पूरी होती है। उसका 59 प्रतिशत स्छळ कतर और **UAE** से आता है और उस सबका एकमात्र रास्ता होर्मुज है। जब होर्मुज बंद हुआ, तो भारत को सीधा झटका लगा। **Brent** के भाव बढ़े, रुपया कमज़ोर हुआ, **petrol** और **diesel** महँगा होने की आशंका बढ़ी। और एक और बात इस युद्ध में भारतीय नागरिक मारे गए। तेल टैंकर **Skylight** पर दो भारतीय नाविक शहीद हुए। डज़व टल्ड पर एक और। यह सिर्फ़ आर्थिक प्रश्न नहीं रहा यह भारतीय खून का प्रश्न बन गया। दाई ओर से देखें तो



तस्वीर और भी साफ़ होती है। भारत का दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से यह रहा है कि हम किसी के खेमे में नहीं हैं। 1947 के बाद से गुटनिरपेक्षता हमारी नीति रही। लेकिन यह एक आदर्श था व्यवहार में हम हमेशा सबसे सस्ते तेल का पीछा करते रहे। रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद हमने रूसी तेल खरीदा। ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद हमने जब तक संभव हुआ, ईरानी तेल खरीदा।

यह व्यावहारिकता है और यही भारत की असली विदेश नीति है। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। होर्मुज़ संकट ने एक सवाल सामने रख दिया है जो भारत टाल नहीं सकता रू क्या भारत केवल उपभोक्ता बना रहेगा, या वह ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति बनाएगा?

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से यह सवाल और भी तीखा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। एक ऐसे देश के लिए, जो वैश्विक शक्ति बनने का दावा करे, ऊर्जा के लिए किसी एक जलमार्ग पर निर्भर रहना और उस जलमार्ग की रक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना पर निर्भर रहना यह कमजोरी है, नीति नहीं। अमेरिका ने क्या किया? उसने अपने **DFC Development Finance Corporation** के ज़रिए **Gulf** में जहाजों को बीमा देने की पेशकश की। उसने अपनी नौसेना को **tanker escort** के लिए तैनात किया। यानी अमेरिकी झंडे के नीचे, अमेरिकी शर्तों पर, तेल बहेगा। यह परोपकार नहीं है। यह **monopoly** है। जो देश अमेरिका के साथ हैं, उनके **tankers** सुरक्षित रहेंगे। जो

नहीं हैं उनके लिए जोखिम है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर **secondary sanction**। चीन के **"shadow fleet"** को निशाना। यह ऊर्जा का हथियार बनाया जा रहा है और होर्मुज़ उस हथियार का ट्रिगर है। भारत के लिए सबक यह है रू जब तक हम किसी और की नौसेना पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए निर्भर हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। मोदी सरकार इस दिशा में कुछ काम कर रही है **IndiaAI Mission** से अलग, ऊर्जा की बात करें तो, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ा है, **strategic petroleum reserves** की बात होती है, रूस से तेल खरीदकर अमेरिकी दबाव के बावजूद अपना रास्ता बनाया। लेकिन यह काफी नहीं है। एक बड़ी शक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब दुनिया के दो महाशक्तियाँ युद्ध में हों और आप तटस्थ रहते हुए भी अपना हित सुरक्षित रख सकें। होर्मुज़ संकट ने एक और चीज़ उजागर

की है जो भारत को सोचनी चाहिए। सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र ईरानी ड्रोन से जल गया। कतर ने **force majeure** घोषित किया। इराक उत्पादन घटा रहा है। यानी सिर्फ़ रास्ता नहीं, स्रोत भी खतरे में हैं। तेल की कीमत +100 प्रति बैरल की तरफ बढ़ रही है। भारत अगर इस समय रिलायंस के जामनगर **refinery** की क्षमता का उपयोग करके यूरोप को **jet fuel eÜport** करे जैसा कि ज़चसमत का विश्लेषण सुझाता है तो यह संकट भारत के लिए एक अवसर भी है। लेकिन यह तभी संभव है जब भारत की नीति स्पष्ट हो, प्रतिक्रियात्मक नहीं।

तो यह युद्ध क्या है?

यह परमाणु प्रसार रोकने का युद्ध नहीं है। यह लोकतंत्र बचाने का युद्ध नहीं है। यह होर्मुज़ की चाबी का युद्ध है। यह तय करने का युद्ध है कि अगले पचास सालों तक दुनिया का तेल किसके झंडे के नीचे बहेगा। अमेरिका अपना जवाब दे चुका है। भारत को अभी अपना जवाब तय करना है और वह जवाब न तो वाशिंगटन की हॉ में हो सकता है, न तेहरान की हॉ में। वह जवाब सिर्फ़ भारत के हित में होना चाहिए। क्योंकि जब तेल की नहरें बंद होती हैं, तो दोस्ती के भाषण काम नहीं आते। काम आता है वह देश जिसके पास अपनी नीति हो, अपनी ऊर्जा सुरक्षा हो, और यह समझ हो कि खेल तेल का है हमेशा से था, आगे भी रहेगा।



मोदी के नेतृत्व में बदला भारत : विकास, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे की नई गति



इंजीनीयर एपी सिंह राजनीतिक संपादक

पिछले एक दशक में भारत ने अंत्योदय और “आत्मनिर्भरता” के विजन के साथ विकास के एक नए युग में प्रवेश किया है। केंद्र सरकार की नीतियां केवल आर्थिक सुधारों तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का कार्य किया है। डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार तक, भारत आज विश्व पटल पर एक सशक्त और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभरा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर सरकार ने न केवल वैश्विक चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है, बल्कि देश को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-बालिका शिशु की देखभाल

केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना पर अधिक बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गोद लिए गांव जयापुर के नागरिकों से कहा कि हमारा मंत्र होना चाहिए ‘बेटा बेटी एक समान’। आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना

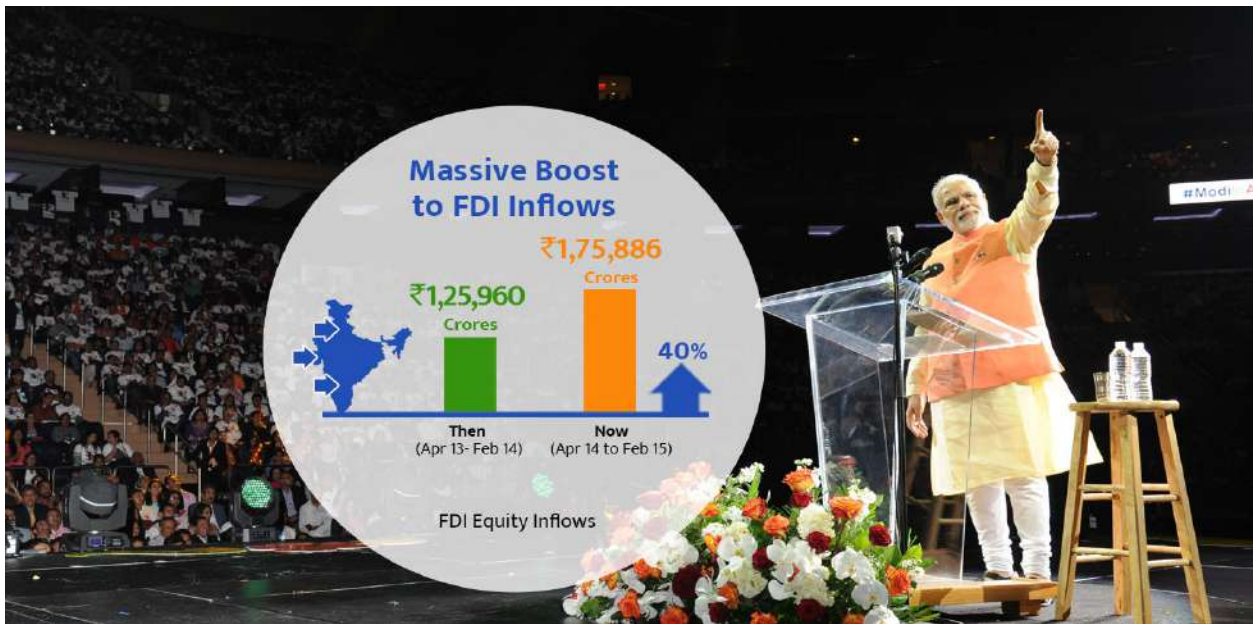
चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप पांच पेड़ लगाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अर्थात् महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल हैं प्रथम चरण में **PC** तथा **PNDT Act** को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों (जहां शिशु लिंग अनुपात कम है) में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना।



बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। एनडीए सरकार कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में हरियाणा के बीबीपुर के एक सरपंच की तारीफ की जिसने **Selfie With Daughter** पहल की शुरुआत की।

जनता को मिली JAM की ताकत: जन धन, आधार और मोबाइल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि **JAM** का विजन, आगामी कई पहलों के लिए बुनियाद का काम करेगा। मेरे लिए **JAM** का मतलब है अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति। खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल। हमारे गरीबों का अधिकतम सशक्तीकरण। जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। पीएम ने कहा कि आजादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं हासिल थीं। इसका मतलब है कि उनके पास न तो बचत कोई जरिया था, न ही संस्थागत कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज एक साल



में 19.72 करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक 16.8 करोड़ रुपये कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 28,699.65 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। रिकॉर्ड 1,25,697 बैंक मित्रों को तैनात किया गया। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि लाखों बैंक खातों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लोगों की आदत में बदलाव लाना था, ताकि वो बैंक खातों का इस्तेमाल शुरू करें। जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर 2014 में 76.8: प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2015 में 32.4: प्रतिशत रह गई। ओवरड्राफ्ट के रूप में अभी तक 131 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया गया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा तथा जनता और सरकारी मशीनरी को प्रोत्साहित करने की उनकी शक्ति द्वारा संभव हुआ। इस विशाल कार्य को मिशन मोड में लिया गया और सरकार तथा जनता की साझेदारी और भागीदारी में पूरा किया गया, जो अनुकरणीय है। लाखों भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए बैंक खाते दिए गए, साथ ही इस पहल ने भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। अब डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जा सकती है। इससे लीकेज और किसी हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हुई है। पहल योजना ने हाल में दुनिया की सबसे बड़ी

डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाती है। इस योजना के तहत 14.62 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने करीब 3.34 करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद की, जिससे हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई। इस समय सरकार करीब 35-40 योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स का उपयोग कर रही है और 2015 में करीब 40,000 करोड़ रुपये लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित किए गए। आम लोगों के लिए बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही एनडीए सरकार ने नागरिकों को बीमा और पेंशन कवर देने के लिए ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति वर्ष महज 12 रुपये में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रतिवर्ष 330 रुपये में जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। अटल पेंशन योजना अंशदान के आधार पर 5000 रुपये प्रति माह तक पेंशन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 9.2 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और करीब 3 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हुए हैं। अटल पेंशन योजना के लिए करीब 15.85 लाख लोगों

ने पंजीकरण कराया है।

विकास के प्रति नवीन दृष्टिकोण: सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ पर अपना विचार साझा किया। हमारे लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हमारा विकास आपूर्ति-उन्मुख रहा है। लखनऊ, गांधी नगर अथवा दिल्ली में एक स्कीम तैयार की गई है। इसे ही आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आदर्श ग्राम के द्वारा इस माडल को आपूर्ति-उन्मुख की बजाए मांग-उन्मुख करना चाहते हैं। स्वयं ग्राम में ही इसकी इच्छा विकसित की जानी चाहिए। हमें केवल अपने विचार में परिवर्तन करना है। हमें लोगों के दिलों को जोड़ना है। सामान्यतः, सांसद राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। लेकिन इसके बाद वे ग्राम में आएंगे। वहां कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। यह परिवार की तरह होगा। ग्राम के लोगों के साथ बैठ कर निर्णय लिया जाएगा। इससे नई उर्जा का संचार होगा और ग्राम को एकजुट करेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना **SAGY** का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए एक यथार्थ रूप देना था। **SAGY** के अंतर्गत, प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और सामाजिक विकास को महत्व देते हुए



इसकी समग्र प्रगति की राह दिखाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर हो। श्रद्धादर्श ग्रामश को स्थानीय विकास एवं सुशासन का संस्थान होना चाहिए जो अन्य ग्राम पंचायतों को प्रेरित करे। ग्रामीणों को शामिल करके और वैज्ञानिक उपायों का लाभ लेते हुए, सांसद के नेतृत्व में एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। उसके उपरांत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और विभागों द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती हैं। 'जन्म स्मरणा' मचवूमतमक ब्वउउपजजमम (स्म) समीक्षा करती है, बदलाव का सुझाव देती है और संसाधनों का चतपवतपजल 'ससवबंजपवद करती है। अब तक, 'लल ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट्स को वरीयता देने के लिए 21 स्कीमों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने संशोद्धित किया है। जिला स्तर पर, सांसद की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रतिभागी विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाती है और प्रगति राज्य सरकार को सूचित की जाती है। यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक सांसद वर्ष 2016 तक एक माडल ग्राम पंचायत के विकास का अग्रणी होगा, इसके बाद वर्ष 2019 तक दो का और वर्ष 2024 तक और पांच का। समूचे देश में अब तक 696 ग्राम पंचायतों को सांसदों द्वारा गोद लिया गया है।

भारतीय उद्यमियों के हौसले हुए बुलंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि

मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में छिपी हुई उद्यमशील उर्जा है। इसे पोषित-पल्लवित करने की जरूरत है, ताकि हम नौकरी चाहने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बनें। एनडीए सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। 'मेक इन इंडिया' पहल भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के हमारे चार स्तंभों पर आधारित है। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। 'मेक इन इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में मान्यता देता है। उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक और सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। सरकार बेहतरीन तकनीक पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटीज के साथ ही हाई-स्पीड कम्युनिकेशन और एकीकृत लॉजिस्टिक व्यवस्था विकसित करना चाहती है। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा गतिविधियों में 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया है और उनकी विस्तृत जानकारी सभी संबंधित पक्षों को दी जा रही है। उद्योग सरकार को एक रेग्युलेटर के रूप में देखने का आदी है। 'मेक इन इंडिया का मकसद उद्योगों के साथ सरकार के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाकर इस सोच को बदलना है। सरकार का दृष्टिकोण एक सुविधाप्रदाता का होगा, और एक रेग्युलेटर का नहीं। सरकार

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक तीन आयामी रणनीति को अपना रही है। ये 3C मॉडल है, जो इन पर काम करेगा कम्पलाईएंस, कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट।

नमामि गंगे उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।' गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40: आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, "अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100: केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया। यह समझते हुए कि गंगा संरक्षण की चुनौती बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी है और इसमें कई हितधारकों की भी



सत्यमेव जयते
Government of India

Saansad Adarsh Gram Yojana



भूमिका है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच एवं केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को बेहतर करने एवं कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किये गए हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को शुरुआती स्तर की गतिविधियों (तत्काल प्रभाव दिखने के लिए), मध्यम अवधि की गतिविधियों (समय सीमा के 5 साल के भीतर लागू किया जाना है), और लंबी अवधि की गतिविधियों (10 साल के भीतर लागू किया जाना है) में बांटा गया है।

भारत के विकास को मिली मजबूती

भारत ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी मिशन तय किया है। ये गांव आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि 1000 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांवों का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है। और, यह काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप और एक वेब डैशबोर्ड के जरिए विद्युतीकरण किए जा रहे गांवों के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि हम गांवों में केवल बिजली को पहुंचता देख सकते हैं, लेकिन यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ गांवों में रह रहे लोगों के सपने, आकांक्षाएं और जीवन में तरक्की करने की बातें भी जुड़ी होती

हैं। यह भुलाना मुश्किल है कि हमारे इतिहास में बिजली जाने की जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें से एक भारत में जुलाई 2012 में घटित हुई। इसने 62 करोड़ लोगों को अंधेरे में डुबो दिया था। इस अंधेरे ने राष्ट्र को घेर लिया, जबकि 24,000 मेगावाट से अधिक की उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है क्योंकि कोयला और गैस जैसे ईंधनों की कमी है। पूरा सेक्टर एक निष्क्रियता के दुष्क्र और चवसपबल चंतंसलेपे में फंस गया जिसमें एक ओर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और अत्यधिक अप्रयुक्त निवेश थे तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी-बड़ी बिजली कटौतियां। पिछले वर्ष जब छव। सरकार सत्ता में आई, तो 2६३ कोयला आधारित बिजली के प्लांटों में (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ट्रैक किए गए अनुसार 100 में से 66 प्लांटों में) कोयले के क्रिटिकल स्टॉक थे जिसका अर्थ यह है कि उनके पास 7 दिन से कम का कोयले का स्टॉक बचा था। इस कठिन स्थिति से उबर आने के बाद, आज देश में एक भी बिजली के प्लांट को कोयले के क्रिटिकल लेवल का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज हुई रफ्तार

एनडीए सरकार के तहत भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साल था। पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के

दौर से उबरते हुए एनडीए सरकार ने ना सिर्फ मैक्रो-इकॉनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार विकास पथ ले आई। भारत की जीडीपी विकास दर कुलांचे भर कर 7.4: हो गई, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। विभिन्न रेटिंग एजेंसी और थिंकटैंक ने अनुमान जताया है कि एनडीए सरकार के तहत अगले कुछ वर्षों में भारत का विकास तेजी से होगा। मजबूत बुनियाद और एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों के चलते मूडीज ने हाल में भारत की रेटिंग को 'स्टेबल' से अपग्रेड करके "पॉजिटिव" कर दिया। ब्रिक्स की शुरुआत होने के बाद कई लोगों को लगने लगा कि "आई" (इंडिया) इस रेस का घोड़ा नहीं है और भारत को संदेह के साथ देखा गया। आज ये भारत ही है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह ब्रिक्स के ग्रोथ इंजन के रूप में उसे शक्ति प्रदान कर रहा है। सरकार द्वारा मैनुफैक्चरिंग पर खास जोर देने के साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पिछले साल निगेटिव ग्रोथ के मुकाबले इस साल 2.1: की दर से बढ़ा। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई (च) में तेज गिरावट देखी गई और ये अप्रैल 2014 में 5.55: के मुकाबले घटकर अप्रैल 2015 में -2.65: प्रतिशत हो गई। एफडीआई इनप्लो ऐतिहासिक गति से बढ़ रहा है। एफडीआई इक्विटी इनप्लो 40: की उछाल दर्ज कर बीते साल के

1,25,960 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 1,75,886 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा भी लगातार गिरावट की स्थिति में है। भारत का चालू खाता घाटा बीते साल जीडीपी के मुकाबले 4.7: के स्तर से इस साल जीडीपी का 1.7: रह गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और ये 309.4 अरब डॉलर से बढ़कर 343.2 अरब डॉलर हो गया। इससे किसी वैश्विक उठा-पटक की स्थिति में भारत को जोखिम से बचने में मदद मिलेगी।

एक खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान
कृषि को तेजी से बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और एनडीए सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाएगी। इस योजना का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी ना किसी तरह के सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की 'प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार' मिले। किसान समूहों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा

देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई। स्थाई आधार पर विशिष्ट फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की पेशकश की गई और इसे देश के सभी 14 करोड़ भूमि खातों के लिए जारी किया जाएगा। तीन वर्ष के चक्र में करीब 248 लाख नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा। घरेलू उत्पादन और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नई यूरिया नीति की घोषणा की गई है और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए गोरखपुर, बरौनी तथा तलचर में खाद फैक्टरी का पुनरोद्धार किया गया है। हाल में हुई बेमौसम बारिश को देखते हुए एनडीए सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कहा कि यदि 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नष्ट हुई है तो किसान मुआवजा पा सकेंगे। इससे पहले किसानों को मुआवजा तभी मिलता था जबकि 50: या इससे अधिक नुकसान हुआ हो। एक 500 करोड़ रुपये के कॉर्पस वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। ये कोष जल्दी खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों की कीमतों को नियंत्रित करने में मददगार होगा। ग्राम ज्योति योजना बिना कटौती के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इससे ना सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि कुटीर उद्योगों और शिक्षा सहित इसका किसानों के पूरे जीवन पर भी भारी असर होगा। डब्ल्यूटीओ वार्ता में एनडीए सरकार के मजबूत और सैद्धान्तिक रुख ने खाद्य सुरक्षा मुद्दा कराने में

किसानों के दीर्घावधि हितों को सुरक्षित किया। आसानी से और रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कृषि ऋण लक्ष्यों को बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। तकनीक बड़े स्तर पर किसानों को ताकत दे रही है। किसान पोर्टल के माध्यम से मौसम की रिपोर्ट से लेकर खाद की जानकारी, सबसे बढ़िया तौर-तरीकों आदि की जानकारी मिल रही है। कृषि में मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। एक करोड़ से अधिक किसानों को सचेत करने और सूचना देने के लिए 550 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।

कायम की अभूतपूर्व पारदर्शिता
देश हित में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। पिछले दशक में हालांकि मनमाने ढंग से फैसले लेने, भ्रष्टाचार और मनमाने ढंग से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कई कहानियां सुनाई दीं, लेकिन पिछले एक वर्ष में स्वगतयोग्य बदलाव देखा गया। कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने अतुलनीय तत्परता दिखाते हुए पारदर्शी और समयबद्ध नीलामी सुनिश्चित की। 67 कोयला ब्लाक की नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया 3.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमें इस तथ्य ने आश्चर्य किया है कि नीलामी की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई। हमें ये पूरी प्रक्रिया मनमाने ढंग से या अतार्किक नहीं लगती है। जाहिर तौर



Leveraging the Power of JAM

Jan Dhan, Aardhar & Mobile

1,80,96,130

Guinness World Record for most bank accounts opened in one week



19.72 crore
Bank accounts opened



16.8 crore
Rupay cards issued



28k crore
Cash Deposits



131 crore
Overdraft

**Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojana**

Provides accident insurance worth
Rs 2 Lakh at Rs 12/ year.

**Pradhan Mantri
Jivan Jyoti Bima Yojana**

Provides life insurance at just Rs 330/year
3 crore - people joined

**Atal Pension
Yojana**

Provides pension upto Rs 5000 / mo
15.85 lakh - people registered



पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि नीलामी की प्रक्रिया किसी खास बोलीदाता को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई। पूर्व में गढ़ी गई जीरो लॉस थिअरी के विपरीत इस बार स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकार के रुख ने भारी लाभ सुनिश्चित किया। डिफेंस बैंड आइडेंटिफिकेशन का जटिल मुद्दा सात साल से अधिक समय से लंबित था, उसका तेजी से समाधान किया गया और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2100 मेगा हर्ट्ज की अच्छी मात्रा को नीलामी में रखा गया। चार विभिन्न बैंड्स— 800 मेगा हर्ट्स, 900 मेगा हर्ट्स, 1800 मेगा हर्ट्स और 2100 मेगा हर्ट्स दृ को एक साथ नीलामी के लिए रखा गया और पहली बार नीलामी के कई दौर हुए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऑपरेटर पूरी जानकारी के साथ निर्णय ले सकें। 80277 करोड़ रुपये के अनुमति प्राप्त आरक्षित मूल्य के मुकाबले नीलामी से 1,09,875 करोड़ रुपये हासिल हुए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के एक इनोवेटिव कदम के तहत पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी मंजूरीयों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू किया। अब मंजूरी पाने के लिए मंत्रालय आने की जरूरत नहीं। आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जा सकती है। जीआईएस आधारित निर्णय सहायक प्रणाली (डीएसएस) से वन मंजूरी आवेदनों पर सुविज्ञ, पारदर्शी, शीघ्र और उम्मीद के मुताबिक निर्णय लेने में मदद मिली। काले धन के मोर्चे पर सरकार ने पहले दिन ही एसआईटी का गठन किया। सरकार स्विस बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है और आईटी

विभाग द्वारा जिन मामलों की जांच की गई है, उनके बारे में जानकारी ले रही है। सरकार ने अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति (टैक्स का अधिरोपण) विधेयक 2015 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में अधोषित विदेशी आय और संपत्ति रखने वालों के लिए कई जुर्मानों तथा सजा के प्रावधान शामिल हैं। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद या बिक्री के लिए पैन का उल्लेख भी अनिवार्य है। एनडीए सरकार ने शिक्षा तथा कौशल विकास को दिया बेमिसाल बढ़ावा। शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई यूनीक उपाये किए गए। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी शिक्षा ऋणों और छात्रवृत्तियों के प्रशासन और निगरानी के लिए एक पूर्ण रूप से आईटी आधारित वित्तीय सहायता प्राप्तिकरण की स्थापना की गई। अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन शुरू किया गया। भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (ळपळ) की शुरुआत हुई। इसके तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में गर्मी और सर्दी के अवकाश के दौरान पूरी दुनिया में सुविख्यात शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों की जानीमानी फैकल्टी, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए स्वयं बड़े स्तर पर मुक्त ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देगा। नेशनल ई-लाइब्रेरी शैक्षणिक सामग्री और ज्ञान के स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देगा। शाला दर्पण एक

मोबाइल टेक्नॉलॉजी है, जो अभिभावकों को स्कूल से जोड़ती है, ताकि वो अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी कर सकें। उड़ान (न्च।।छ) बालिका शिक्षा के प्रति समर्पित है, ताकि छात्राओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके। ईशान विकास का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के चुनिंदा स्कूली विद्यार्थियों और इंजीनियरिंग छात्रों को उनकी छुट्टियों के दौरान आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर से जोड़ना है। यूएसटीडीएडी ने परंपरागत कला और शिल्पकारी में कौशल और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों की क्षमता को बढ़ाना, परंपरागत कला और शिल्प का मानकीकरण, उनका दस्तावेजीकरण और उन्हें बाजार से जोड़ना है। स्किल इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी कितना महत्व देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार ने हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तत्काल एक अलग कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया। अभी तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 'स्कूल टू स्किल' कार्यक्रम के तहत कौशल प्रमाणपत्रों को अकादमिक समानता दी गई। 1500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी गई। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तीन वर्षों में दस लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। अप्रेंटिसशिप कानून में संशोधन के जरिए ऑन-जॉब ट्रेनिंग के अवसरों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ किया गया। सरकार अगले ढाई सालों में 50: स्टाइपेंड शेयर करके एक लाख अप्रेंटिसशिप को समर्थन देगी। सरकार की योजना है कि मौजूदा 2.9 लाख के मुकाबले अगले कुछ वर्षों में 20 लाख से अधिक अप्रेंटिस देने की है। राष्ट्रव्यापी अवसर उपलब्ध कराने के लिए नेशनल करियर सेंटर की शुरुआत हुई और एक स्थान पर सभी ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने का काम करेगी। ये केंद्र युवाओं को करियर संबंधी उपयोगी सामग्री और स्व-मूल्यांकन के साधन भी उपलब्ध कराएंगे। युवाओं के लिए सलाहकारों का एक नेटवर्क भी उपलब्ध होगा।

शुभकामनाएं

एनएचपीसी का हरित ऊर्जा नेतृत्व स्वर्ण जयंती वर्ष

- ⚡ **180 मेगावाट से 8247.18 मेगावाट तक की यात्रा :** अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 30 नवीकरणीय ऊर्जा पावर स्टेशनों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति।
- ⚡ **सुदृढ़ वित्तीय प्रदर्शन:** अपनी स्थापना के बाद से निरंतर सुदृढ़ परिणाम प्रदर्शित कर रही है।
- ⚡ **16 सक्रिय परियोजनाएं :** संधारणीय भविष्य के लिए, लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का निर्माण कर रही है।
- ⚡ **एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देना:** वर्ष 2032 तक 23,000 मेगावाट और वर्ष 2047 तक 50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य।
- ⚡ **भारत की दो सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण:**
 - ⚡ दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना: 2,880 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश में।
 - ⚡ सुबनसिरी लोअर परियोजना: 2,000 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश और असम में।
- ⚡ **नवरत्न का दर्जा:** कार्यनीतिक महत्व को मान्यता देते हुए 30 अगस्त, 2024 को प्रदान किया गया।
- ⚡ **भविष्य के लिए विजन:** एनएचपीसी संधारणीय ऊर्जा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन के प्रति समर्पित है।

सिक्किम में स्थापित परियोजनाएं / पावर स्टेशन

तीस्ता -V पावर स्टेशन 510 मेगावाट
रंगीत पावर स्टेशन 60 मेगावाट
तीस्ता -V परियोजना 500 मेगावाट
रंगीत IV परियोजना 120 मेगावाट

पश्चिम बंगाल में स्थापित पावर स्टेशन

तीस्ता लो डैम III पावर स्टेशन 132 मेगावाट
तीस्ता लो डैम IV पावर स्टेशन 160 मेगावाट



एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवनिर्माण उद्यम)

क्षेत्रीय कार्यालय सितीगुड़ी विद्युत नगर सेक्टर-8 टाउनशिप सितीगुड़ी पश्चिम बंगाल 734015
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564 | वेबसाइट: www.nhpcindia.com

आइए,

हम सब मिलकर हरित ऊर्जा में नेतृत्व की विरासत का उत्सव मनाएं !

<https://www.nhpcindia.com>

Join us:     

केंद्रीय बजट में राजकोषीय संयम पर दिया गया विशेष बल



केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च और घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के उपायों की घोषणा नई दिल्ली। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश किया है, जिसमें बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च और घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के उपायों की घोषणा की गई है। देश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के इस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4: की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, लेकिन अगले वर्ष आर्थिक विस्तार में थोड़ी कमी आएगी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यातकों पर लगाए गए 50: टैरिफ का प्रभाव अधिक दिखने लगेगा। बजट में राजकोषीय संयम पर विशेष बल दिया गया है, जिसका लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए घाटे को कम करना है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। बजट घोषणाओं से प्राप्त पांच प्रमुख निश्कर्ष इस प्रकार हैं: बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च, रक्षा व्यय में वृद्धि सड़क, बंदरगाह और रेलवे परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे पर नरेंद्र मोदी सरकार का पिछले एक दशक से मुख्य ध्यान रहा है, और यह बजट इन क्षेत्रों के लिए आवंटन को बढ़ाना जारी रखता है। 11 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य लगभग 9: बढ़कर 11.1 ट्रिलियन रुपये से 12.2 ट्रिलियन रुपये (133.1 बिलियन डॉलर 105 बिलियन 22 **प्राइम सेक्टर (मासिक पत्रिका) मार्च 2026, दिल्ली**

पाउंड) हो गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के मद्देनजर रक्षा पर होने वाले व्यय में भी 20: से अधिक की वृद्धि हुई है। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और अर्धचालकों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना भारत में निजी निवेश में मंदी और विदेशी पूंजी के पलायन के बीच, सरकार ने सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, वस्त्र और दुर्लभ धातुओं सहित सात रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सीतारामन ने घोषणा की कि दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा पूर्व में ओडिशा सहित चार राज्यों में दुर्लभ खनिजों के लिए समर्पित गलियारे स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणा नवंबर में घोषित 73 अरब रुपये की दुर्लभ खनिज योजना को भारत की मंजूरी के बाद की गई है। इस बजट में 436 मिलियन डॉलर के व्यय के साथ एक दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत भी की गई है, जिसका उद्देश्य उपकरण और सामग्री का उत्पादन करना और पूर्ण-स्टैक बौद्धिक संपदा का डिजाइन तैयार करना है। भारत विदेशी क्लाउड कंपनियों को, जो देश में डेटा सेंटर में निवेश करती हैं और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं, 2047 तक कर छूट देने का प्रस्ताव भी दे रहा है। भारत अरबों डॉलर के डेटा सेंटर निवेश को आकर्षित कर रहा है, उदाहरण के लिए पिछले साल गूगल ने दक्षिण भारत में एक सुविधा केंद्र में 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। यह अत्यधिक पूंजी-गहन क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक

राजकोषीय निश्चितता प्रदान करता है, जिससे निवेश की व्यवहार्यता में काफी सुधार होता है और क्षमता निर्माण में तेजी आती है, ऐसा अर्नस्ट एंड यंग इंडिया की रितिका लोगानी गुप्ता ने कहा। बजट में श्रम प्रधान वस्त्र उद्योग में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए नए मेगा-टेक्सटाइल पार्कों की भी घोषणा की गई है – उम्मीद है कि पिछले सप्ताह हुए भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के बाद वैश्विक बाजार तक अधिक पहुंच से इस उद्योग को लाभ होगा। कोई नई कर छूट नहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण निर्यात में आई मंदी के बीच, भारत ने समुद्री भोजन जैसे उद्योगों के लिए शुल्क-मुक्त इनपुट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो प्रमुख निर्यात क्षेत्र हैं। लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में उपयोग होने वाले इनपुट पर भी सीमा शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन व्यक्तिगत आय पर प्रत्यक्ष कर कटौती की कोई घोषणा नहीं की गई है। इसकी उम्मीद पहले से ही थी क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले साल आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी थी, जिससे पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय को छोड़कर 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर-मुक्त हो गई थी। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का युक्तिकरण भी किया गया था, जिससे नई कटौती के लिए राजकोषीय गुंजाइश बहुत कम रह गई थी।

**प्राइम सेक्टर डेस्क
प्रस्तुति**

भारत एआई में अवसर और भविष्य की रूपरेखा देखता है-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



प्रशांत दत्त मिश्रा

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट भारत में आयोजित हो रहा है, जो मानवता के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़े तकनीकी प्रतिभा भंडार और समृद्ध प्रौद्योगिकी-सक्षम इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल नई प्रौद्योगिकियों का निर्माण करता है, बल्कि उन्हें अभूतपूर्व गति से अपनाता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उत्सुक हैं और उनकी ओर से उन्होंने शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों, वैश्विक एआई इकोसिस्टम के नेताओं और नवप्रवर्तकों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना न केवल देश के लिए बल्कि विकासशील

देशों के लिए भी गर्व की बात है। पीएम मोदी ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में एआई जगत की जानी-मानी हस्तियां एक साथ आई हैं। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और विश्व भर के प्रतिष्ठित प्रतिभागी शामिल होने से इस आयोजन की सफलता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। उन्होंने शिखर सम्मेलन में युवा पीढ़ी की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे उन्हें नया आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा कि जहां नई तकनीकों को अक्सर शुरुआत में संदेह का सामना करना पड़ता है, वहीं जिस गति और विश्वास के साथ विश्व भर के युवा एआई को अपना रहे हैं, उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने एआई शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी के प्रति उत्साह, विशेष रूप से युवा प्रतिभाओं की बड़ी भागीदारी की भी सराहना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कृषि, सुरक्षा, दिव्यांगजनों की सहायता और बहुभाषी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में प्रस्तुत समाधान श्रेष्ठ इन इंडिया की ताकत को दर्शाते हैं और एआई क्षेत्र में भारत की नवोन्मेषी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि

मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों में एक ऐसा मोड़ आता है जो सभ्यता की दिशा बदल देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षण विकास की गति को बदल देते हैं और सोचने, समझने और काम करने के तरीकों को बदलाव लाते हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के ऐसे दौर में अक्सर वास्तविक प्रभाव तुरंत समझ में नहीं आता। उन्होंने याद दिलाया कि जब पथरों से पहली बार चिंगारी निकली थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वही चिंगारी सभ्यता की नींव बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि जब बोली जाने वाली भाषा को पहली बार लिपि में बदला गया था, तब किसी को यह एहसास नहीं था कि लिखित ज्ञान, भविष्य की प्रणालियों की रीढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि जब पहली बार वायरलेस तरीके से सिग्नल भेजे गए थे, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया एक-दूसरे से जुड़ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता के ऐतिहासिक मोड़ के समान ही व्यापक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि आज जो देखा और अनुमान लगाया जा रहा है, वह इसके प्रभाव के केवल प्रारंभिक संकेत हैं।



संदर्भ में भी है क्योंकि भविष्य में किस प्रकार के रोजगार सृजित होंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। उन्होंने कहा कि एआई में कार्य का भविष्य पूर्वनिर्धारित नहीं है, बल्कि सामूहिक निर्णयों और कार्यों पर निर्भर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि कार्य का भविष्य एक नया अवसर है, जो एक ऐसे युग का प्रतीक है जहां मनुष्य और बुद्धिमान प्रणालियां सह-निर्माण, सह-कार्य और सह-विकास करेंगी। उन्होंने कहा कि एआई कार्य को अधिक स्मार्ट, अधिक कुशल और अधिक प्रभावशाली बनाएगा जिससे बेहतर डिजाइन, तेजी से निर्माण और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि एआई से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उच्च मूल्य, रचनात्मक और सार्थक अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे नवाचार, उद्यमिता और नए उद्योगों के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कौशल विकास, पुनर्विकास और आजीवन सीखने को जन आंदोलन बनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काम का भविष्य समावेशी, भरोसेमंद और मानव-केंद्रित होगा और यदि मानवता एक साथ आगे बढ़ती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि सूर्य की रोशनी सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ देश और कंपनियां एआई को एक रणनीतिक संपत्ति मानती हैं जिसे गोपनीय रूप से विकसित किया जाना चाहिए, वहीं भारत का मानना है कि एआई से दुनिया को तभी लाभ होगा जब इसे साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओपन कोड और साझा विकास से लाखों युवा एआई को बेहतर और सुरक्षित बनाने में सक्षम होंगे। उन्होंने एआई को वैश्विक हित के रूप में विकसित करने के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। वैश्विक मानकों की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि डीपफेक और मनगढ़ंत सामग्री खुले समाजों को अस्थिर कर रही है। खाद्य पदार्थों पर लगे पोषण लेबल का

एआई मशीनों को बुद्धिमान बना रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मानव क्षमता को कई गुना बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इस बार यह अंतर अभूतपूर्व गति और अप्रत्याशित पैमाने में निहित है। उन्होंने कहा कि पहले, प्रौद्योगिकी के प्रभाव को नजर आने में दशकों लग जाते थे, लेकिन आज मशीन लर्निंग से लेकर लर्निंग मशीनों तक का सफर तेज, गहरा और व्यापक है। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी की आवश्यकता है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों को सौंपी जाने वाली एआई के स्वरूप के बारे में भी चिंता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि एआई भविष्य में क्या कर सकती है, बल्कि यह है कि मानवता वर्तमान में एआई का उपयोग कैसे करना चाहती है। परमाणु ऊर्जा का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता ने इसकी विनाशकारी क्षमता और इसके सकारात्मक योगदान दोनों को देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक परिवर्तनकारी शक्ति है, यदि दिशाहीन हो तो यह व्यवधान उत्पन्न करती है, लेकिन सही दिशा मिलने पर यह समाधान बन जाती है। श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य इस बात पर विचार-विमर्श करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को

मशीन-केंद्रित के बजाय मानव-केंद्रित, संवेदनशील और उत्तरदायित्वपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रति भारत का दृष्टिकोण इस शिखर सम्मेलन के विषय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में स्पष्ट रूप से झलकता है और यही भारत के लिए आदर्श भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मनुष्य केवल एआई के लिए डेटा पॉइंट या कच्चा माल बनकर न रह जाएं, इसलिए एआई का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एआई को समावेशन और सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई को खुली छूट दी जानी चाहिए लेकिन कमान मानव हाथों में ही रहनी चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना जीपीएस से की, जो मार्ग सुझाता है लेकिन अंतिम निर्णय उपयोगकर्ता पर छोड़ देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज मानवता एआई को जिस दिशा में ले जाएगी, वही भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा कि भारत का यह मानव विजन 21वीं सदी की एआई-संचालित दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इससे कितने रोजगार सृजित होंगे। यही स्थिति आज एआई के

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल सामग्री पर भी प्रामाणिकता लेबल होना चाहिए ताकि लोग वास्तविक और कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री के बीच अंतर कर सकें। श्री मोदी ने एआई से टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के बढ़ते उपयोग को देखते हुए वॉटरमार्किंग और स्पष्ट स्रोत मानकों की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि प्रौद्योगिकी में शुरू से ही विश्वास का निर्माण होना चाहिए।



राहुल गांधी ने समिट को

बताया पीआर स्टंट भारत में आयोजित एआई समिट को राहुल गांधी ने एक पीआर स्टंट बताया है। एआई इम्पैक्ट समिट में कथित तौर पर चीनी निर्मित रोबोटिक कुत्ते को अपना आविष्कार बताकर पेश करने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने इसे ध्वव्यस्थित जनसंपर्क तमाशा करार दिया, जहां चीनी उत्पादों का प्रदर्शन करके भारतीय डेटा को बेचा जा रहा है। एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय, एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा है – भारतीय डेटा बिक्री के लिए रखा गया है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर लगा आरोप

एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर लगा चीनका रोबो डॉग को अपना बताकर समिट में पेश करने का आरोप इसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही जिसके बाद बुधवार शाम को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर माफी मांगी है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यह गलतफहमी की वजह से हुआ था। साथ ही यूनिवर्सिटी ने बताया है कि उसने समिट से अपना स्टॉल

खाली कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने लिखा कि हमारे स्टॉल पर मौजूद हमारी एक प्रतिनिधि को तकनीकी जानकारी सही तरीके से नहीं मिली थी। कैमरे पर आने के उत्साह में उन्होंने उत्पाद से जुड़ी कुछ गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति भी नहीं थी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस स्थिति को समझें, क्योंकि हमारा मकसद किसी भी तरह से इस इनोवेशन को गलत तरीके से पेश करना नहीं था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी शैक्षणिक ईमानदारी, पारदर्शिता और अपने काम की जिम्मेदार प्रस्तुति को लेकर प्रतिबद्ध है। आयोजकों की भावना का सम्मान करते हुए हमने कार्यक्रम स्थल खाली कर दिया है। राजधानी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एआई समिट के दूसरे दिन उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण बढ़ते स्वचालन और उससे उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी के खतरे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार तकनीक को बढ़ावा देने

के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका दावा है कि एआई के अनियंत्रित उपयोग से आईटी, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है। युवाओं ने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि प्रभावित होने वाले कामगारों के पुनर्वास और कौशल विकास के लिए क्या ठोस योजना है। जब प्रदर्शनकारी समिट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कई प्रमुख युवा नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें देर शाम रिहा किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे तकनीक के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसी तकनीक का विरोध करेंगे जो इंसान के हाथ से निवाला छीन ले। उन्होंने मांग की कि सरकार को एआई अपनाने से पहले एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो हर भारतीय युवा के रोजगार की गारंटी दे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा।

राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप



सुनील नेगी

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी जेफरी एपस्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अदानी से जुड़े मामलों पर बोले। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला। हरदीप पुरी ने कहा कि एपस्टीन से उनकी मुलाकात केवल फ्लूच मौकों पर, वह भी एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरें रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अनिराधार आरोप लगा रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण की गलत बातों को कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी के इस भाषण से पहले विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था कि उनके नेता को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के

**एपस्टीन से तीन या चार
बार हुई थी मुलाकात —
राहुल के आरोपों के
बाद बोले हरदीप पुरी,
कांग्रेस ने पूछे छह
सवाल**

अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने के बाद बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की संस्मरणों की किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश उद्धृत करने की कोशिश की थी। इसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था अप्रकाशित अंश को कोट नहीं किया जा सकता। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि उसके नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस विवाद के बढ़ने के बाद विपक्षी नेताओं ने बताया कि उन्होंने ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस विवाद के बाद बुधवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो बजट पर चर्चा

के दौरान राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ही अनिल अंबानी का परिचय अमेरिकी निवेशक और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कराया था। उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन हैं अनिल अंबानी, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जेल में क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनका नाम एपस्टीन फाइल्स में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहूंगा, जिन्होंने उन्हें एपस्टीन से परिचय कराया था। मैं जानता हूँ कि किसने परिचय कराया और हरदीप पुरी जानते हैं कि किसने उनका परिचय कराया।

पुरी ने राहुल के बयान पर क्या कहा

संसद में एपस्टीन फाइल और हरदीप पुरी को जोड़कर दिए गए बयान के बाद, हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज उन्होंने (राहुल गांधी) सदन की कार्यवाही के दौरान एपस्टीन फाइल्स के संदर्भ में मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा कि एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें रिलीज हुई हैं और मैं न्यूयॉर्क में आठ साल रहा। मैं वहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनकर

2009 में पहुंचा था और 2017 में मैं मंत्री बना और आठ सालों में संभवतः तीन या चार मीटिंग का संदर्भ है। हरदीप पुरी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी मेरे पास आए और कहा कि शकुल नाम दिलचस्प जगह पर आए हैं। उसके बाद मैंने युवा नेता राहुल गांधी को बताने का फैसला किया और मैंने कहा कि उन्हें एक नोट भेजूंगा। उन्होंने कहा कि इस नोट में मैंने लिखा कि अमेरिका

बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए पुरी से कुछ छह सवाल पूछे। पवन खेड़ा ने लिखा कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके फ्लैपकार्ड ने उन्हें रीड हॉफमैन से मिलवाया था। लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा, वह ज्यादा मायने रखता है। 4 अक्टूबर, 2014 को एपस्टीन ने हरदीप को ईमेल किया। रीड से मुलाकात हुई? हरदीप ने कुछ ही घंटों में जवाब दिया। रीड आज दोपहर एक

3. हरदीप उससे मुलाकात की जानकारी क्यों डिस्कस कर रहे थे?
4. एपस्टीन को दोस्त करके क्यों संबोधित किया गया?
5. एपस्टीन हरदीप के लिए क्या करवा रहा था?
6. अगर उनका संबंध महज संयोगवश या सतही था, तो हरदीप एपस्टीन से शसलाह क्यों मांग रहे थे?
पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े अपने रिकॉर्ड



में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर होने के कुछ महीने बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (आईपीआई) में आमंत्रित किया गया था। मैं आईसीएम में सेक्रेटरी जनरल था। इसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आईसीएम आईपीआई का प्रोजेक्ट था। आईपीआई में मेरे बॉस टेरियल रोड लार्सन उस कुख्यात व्यक्ति, एपस्टीन को जानते थे। आईपीआई और आईसीएम के डेलिगेशन के तौर पर मैं एपस्टीन से कुछ मौकों पर मिला। मैं तीन या अधिकतम चार बार उनसे मिला। आईपीआई और आईसीएम अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखता था और एपस्टीन इसका हिस्सा नहीं थे। हरदीप पुरी का कहना था कि एपस्टीन से जुड़े मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और जो भी मेल से बातचीत हुई है वो सार्वजनिक है। हरदीप सिंह पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने बार फिर उनपर हमला

मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को में हूँ। मेरे दोस्त, तुम तो चीजें करवा देते हो। कोई सलाह? — इसके बाद खेड़ा ने एक्स पर की गई पोस्ट में छह सवाल पूछे, ये सवाल थे — 1. एपस्टीन को रीड के साथ हरदीप की मुलाकात के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया?

क्या एपस्टीन ही वह कॉन्टेक्ट था जिसने रीड हॉफमैन के साथ मुलाकात करवाई थी?

की एक बड़ी नई खेप सार्वजनिक की। यह खुलासा उस कानून के तहत दोबारा शुरू किया गया है, जिसका मकसद यह साफ करना है कि सरकार को उसकी कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण और उसके अमीर और प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों के बारे में क्या जानकारी थी। अमेरिका के उप-अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लॉश ने बताया था इस ताजा खुलासे में 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं।



-किरेन रिजिजू बोले- राहुल के आरोप निराधार

हरदीप पुरी पर लगाए गए आरोपों के बाद राहुल गांधी के भाषण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि राहुल गांधी शनिराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके भाषण की गलत बातों को कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। रिजिजू ने कहा कि बजट पर भाषण देते समय राहुल गांधी बिना किसी तर्क, बिना किसी सबूत और बिना किसी नोटिस के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पूरे भाषण में जो भी गलत बातें कही हैं, सब हटाई जाएंगी और जो भी असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उन्हें भी हटाया जाना चाहिए। खासकर जो भी झूठ उन्होंने कहा है, गलत बातों का जिक्र किया है और आरोप लगाए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी याद दिलाया कि इस देश को कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। तब राहुल गांधी ने कहा कि किसी ने भारत को बेच दिया और किसी ने भारत को खरीद लिया। भारत को खरीदने या बेचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने “पूरी तरह से आत्मसमर्पण” कर दिया है। गांधी ने कहा कि यह ये दुखद है कि 1.4 अरब लोगों का भविष्य शबाजपा के वित्तीय स्ट्रक्चर की रक्षा के लिए दांव पर



लगा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचेंगे। उन्होंने भारत को इसलिए बेचा है क्योंकि वे उनका दम घोट रहे हैं। मैंने कहा था कि जब आपका दम घुटता है, तो आंखों में डर दिखाई देता है। आप इसे प्रधानमंत्री की आंखों में देख सकते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत ने टैरिफ के मामले में घुटने टेक दिए हैं, अपना डेटा सौंप दिया है और डिजिटल व्यापार नियमों पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के डेटा का कोई लोकलाइजेशन नहीं है, अमेरिका को लगातार डेटा मिल रहा है। हमारी सबसे कीमती संपत्ति उसे सौंप दी गई है।

बीजेपी ने लगाया राहुल पर झूठ बोलने का आरोप

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले जहरीला झूठ बोलो और फिर विदेश उड़ जाओ। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी पर उग्रता के साथ

झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर संसद में सड़क छाप आचरण करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कभी संसद सत्र लोकतंत्र के सर्वोच्च मानकों का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज राहुल गांधी के व्यवहार, भाषा और शैली ने संसदीय मर्यादा को सबसे निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चेतावनी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से झूठे आरोप लगाए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक, संसद में बोलने की एक मर्यादा और शालीन भाषा होती है, जिसका पालन हर सदस्य को करना चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार और असंसदीय मर्यादा का पालन न करना दिखाता है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार से बौखला गई है। उन्होंने राहुल गांधी होशो-हवास खो चुके हैं। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को शायद यह भी ध्यान नहीं है कि वे किस पद पर हैं और क्या बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने मनोज नरवण की किताब को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूछ रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन इस मामले में पहले किताब के प्रकाशक और फिर खुद लेखक की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से साफ हो गया है कि गलत बयान राहुल गांधी ने ही दिया।



एनएमडीसी अनुसंधान एवं विकास केंद्र और आईआईटी हैदराबाद के बीच समझौता



जिम्मेवार खनिज एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने भारत के खनिज और धातु क्षेत्र के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (आईआईटीएच) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। खनिज प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (आरएंडडी) संजीव साही और आईआईटी हैदराबाद के डीन (प्रायोजित अनुसंधान और परामर्श) ने आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रो. बी. एस. मूर्ति की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अयह साझेदारी फील्ड की विशेषज्ञता और अकादमिक उत्कृष्टता के बीच एक मजबूत सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है। एनएमडीसी और आईआईटी हैदराबाद एक साथ मिलकर लौह अयस्क बेनीफिशिएशन और एग्लोमेरेशन, हरित इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकियों, स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग करके वैकल्पिक लौह निर्माण, और खनन और धातुकर्म प्रक्रियाओं के उन्नत मॉडलिंग और सिमुलेशन में अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। यह सहयोग प्राथमिक और

शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग होगा मजबूत, खनन नवाचार को मिलेगी नई दिशा

माध्यमिक स्रोतों से महत्वपूर्ण और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के उत्खनन में नए रास्ते भी बनाएगा, जिससे भारत की खनिज सुरक्षा और संसाधन उपलब्धता सुदृढ़ होगी। खनन क्षेत्र में तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन के साथ सं. रेखित, एमओयू स्वायत्त वाहन चालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, (आईओटी), माइनिंग 4.0 फ्रेमवर्क और ड्रोन-सक्षम सर्वेक्षण और निगरानी में अनुसंधान और पायलट पहलों को चलाएगा। परिचालन शक्ति को अनुसंधान-संचालित नवाचार के साथ एकीकृत करके, गठजोड़ का उद्देश्य टिकाऊ, प्रौद्योगिकी-चालित समाधान प्रदान करना है जो भारत के विकासशील खनिज परिदृश्य में दक्षता, उत्पादकता और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ाता है। अमिताभ मुखर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी ने समझौता ज्ञापन संपन्न होने के अवसर

पर कहा, "आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन उद्योग-अकादमिक गठजोड़ नवाचार के प्रति एनएमडीसी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। आईआईटी हैदराबाद की अनुसंधान उत्कृष्टता और एनएमडीसी की डोमेन विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, यह साझेदारी खनन, खनिज प्रसंस्करण और उभरते क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाएगी, जो सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन में योगदान देगी। यह साझेदारी नवाचार-संचालित विकास के लिए एनएमडीसी की प्रतिबद्धता और अनुसंधान को प्रभावशाली औद्योगिक अनुप्रयोगों में बदलने में आईआईटी हैदराबाद की भूमिका को रेख. कित करती है। दोनों संस्थान साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन में योगदान देंगे। विशेष रूप से, यह सहयोग एक ऐतिहासिक क्षण में आया है क्योंकि एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने भारत के खनिज विकास के इतिहास में समर्पित योगदान के 50 वर्ष पूरे किए हैं, जो अनुसंधान में उत्कृष्टता की अपनी विरासत और तकनीकी उन्नति के अपने निरंतर प्रयासों को और अधिक मजबूती प्रदान करता है।

उमरेड पावर ट्रांसमिशन का हस्तांतरण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को

नई दिल्ली। आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL), जो कि REC Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSU) है, ने महाराष्ट्र के अंतरा-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) परियोजना के अंतर्गत स्थापित परियोजना-विशेष कंपनी (SPV) 'उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का सफल बोलीदाता Maharashtra State Electricity

एवं वितरण) विजय कुलकर्णी द्वारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की कंपनी सचिव विनीता श्रीवाणी एवं मुख्य अभियंता (TBCB) अमित नाइक को किया गया। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी तथा महाराष्ट्र राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (STU) के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। परियोजना की निर्धारित कार्यान्वयन अवधि 24 माह है। इस योजना के अंतर्गत उमरेड में 400/220/132 केवी क्षमता का एक नवीन सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा।

में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्ष 1969 में स्थापित त्म लिमिटेड ने अपने कार्य संचालन के 55 से अधिक वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण सहित संपूर्ण विद्युत मूल्य श्रृंखला के विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में त्म ने ऊर्जा क्षेत्र से इतर अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों जैसे हवाई अड्डे, मेट्रो, रेल, बंदरगाह एवं पुलकृमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।



Transmission Company Limited को 26 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से हस्तांतरण कर दिया। यह परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित की गई। RECPDCL ने इस प्रक्रिया में बोली प्रक्रिया समन्वयक की भूमिका निभाई। प्रतिस्पर्धी बोली के उपरांत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को इस परियोजना के विकास हेतु चयनित किया गया। परियोजना का क्रियान्वयन 'बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOOT) मॉडल के आधार पर किया जाएगा। एसपीवी का हस्तांतरण आरईसीपीडीसीएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष (ट्रांसमिशन

साथ ही उमरेड (नवीन) से अतिरिक्त बुटीबोरी (प्रस्तावित) तक लगभग 51 किलोमीटर लंबी 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तथा कोलारी (विद्यमान) से उमरेड (नवीन) तक लगभग 38 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 400/220/132 केवी स्तर पर विभिन्न लाइनों की स्पष्ट (लाइन-इन, लाइन-आउट) व्यवस्था एवं अन्य संबद्ध कार्य भी इस परियोजना में शामिल हैं।

REC लिमिटेड के बारे में :

REC Limited एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो देशभर में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण एवं विकास

RECPDCL के बारे में: REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL), REC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों एवं ऊर्जा विभागों को ज्ञान-आधारित परामर्श सेवाएं तथा परियोजना क्रियान्वयन में विशेषज्ञ सहयोग प्रदान करती रही है। RECPDCL ने

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में भी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, RECPDCL अंतरा-राज्यीय एवं राज्यांतर्गत ट्रांसमिशन परियोजनाओं तथा रीबंडलिंग परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) प्रक्रिया के अंतर्गत बोली प्रक्रिया समन्वयक (BPC) के रूप में कार्य कर रही है। अपनी विशेषज्ञ परामर्श, परियोजना कार्यान्वयन एवं लेनदेन सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से RECPDCL देश के विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आईएमएफए ने ओडिशा में टाटा स्टील के फेरोक्रोम प्लांट का किया अधिग्रहण

नई दिल्ली। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज ने ओडिशा में टाटा स्टील से 707.26 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर एक फेरोक्रोम प्लांट का एक्विजिशन पूरा कर लिया है। कलिंगनगर में 115 एकड़ में फैली, नई एक्वायर की गई फैसिलिटी में चार फर्नेस हैं जो हर साल 100,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) प्रोडक्शन कर सकती हैं, जो लगभग एक साल में आंशिक रूप से बनी पांचवीं फर्नेस के चालू होने पर बढ़कर 150 हजार टीपीए

हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू 707.26 करोड़ रुपये है, जिसमें जी एस टी और नेट वॉकिंग कैपिटल के साथ 610 करोड़ रुपये का बेस



कंसीडरेशन शामिल है, और इसे पूरी तरह से इंटरनल एक्रुअल्स से फंड किया गया है। भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर वाली इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड (आईएमएफए) भारत की सबसे बड़ी पूरी तरह से इंडीग्रेटेड वैल्यू-एडेड फेरो क्रोम प्रोड्यूसर है।

आरईसी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड्स जीते



आरईसी लिमिटेड, जो विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसई और एक प्रमुख एनबीएफसी है, को अपनी प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहल 'डॉक्टर आपके दरवाजे' के लिए 'पीएसयू में सर्वश्रेष्ठ सीएसआर परियोजनाओं' श्रेणी के तहत वैश्विक सीएसआर उत्कृष्टता और नेतृत्व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से है। यह अवॉर्ड आरईसी की तरफ से

रीजनल ऑफिस मुंबई के चीफ प्रोग्राम मैनेजर, आलोक सिंह और चीफ मैनेजर (सीएसआर) विशाल सुदेश ने 18 फरवरी 2026 को वर्ल्ड सीएसआर डे पर ताज लैंड्स एंड, मुंबई में आयोजित ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड्स के 15वें एडिशन के दौरान लिया। यह पहचान असरदार सामाजिक विकास में एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर के तौर पर आरईसी की पोजिशन को और मजबूत करती है। इस फाइनेंशियल ईयर में, आरईसी के सीएसआर कामों

को कई अवॉर्ड मिले हैं, जिनमें एसोचौम सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड 2024, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से सीएसआर अवॉर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, और बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स दृष्टि से पब्लिक सेक्टर के लिए फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 शामिल हैं। ये सभी सम्मान असरदार सोशल डेवलपमेंट और जरूरतमंद समुदायों में जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आरईसी के मजबूत कमिटमेंट को दिखाते हैं।

एसजेवीएन ने एमएसएमई के लिए विशेष वेंडर डेवलपमेंट मीट 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया



शिमला। एसजेवीएन ने नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशेष वेंडर डेवलपमेंट मीट 2026 का सफल आयोजन किया। भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथि भूपेंद्र गुप्ता ने, अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक), सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त), चंद्र शेखर यादव, कार्यकारी निदेशक विभागाध्यक्ष (मानव संसाधन) तथा कारपोरेट मुख्यालय, शिमला, संपर्क कार्यालय, दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी तथा वेंडर मीट से संबद्ध अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भूपेंद्र गुप्ता ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि विशेष वेंडर डेवलपमेंट मीट 2026 नई सहभागिता बनाने, नए अवसर तलाशने तथा आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से, एसजेवीएन ने वेंडर सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए 36 वेंडर डेवलपमेंट मीट आयोजित किए हैं। इस बात पर बल देते हुए कि एमएसएमई विकास एसजेवीएन की सफलता का एक आवश्यक हिस्सा है, उन्होंने अनुसूचित

जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को आर्थिक पारितंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने तथा एसजेवीएन की प्रापण प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक) ने वेंडर मीट को संबोधित करते हुए कहा कि एसजेवीएन अपने प्रापण लक्ष्यों को पूर्ण करने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित एमएसई सार्वजनिक प्रापण का लाभ प्रदान करने के लिए एमएसएमई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विजन में योगदान देते हुए यह आत्मनिर्भर, भविष्योन्मुखी और समावेशी एमएसएमई नेटवर्क को बढ़ावा देती हैं। सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त) ने कहा कि एसजेवीएन, एमएसएमई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं, के साथ निकटता से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी के परिकल्पित विकसित भारत 2047 के विजन को पूर्ण करने में एमएसएमई प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एसजेवीएन एमएसएमई के साथ नॉलेज शेयरिंग और उत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर आधारित एक सहयोगी केन्द्र बनने

के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्र शेखर यादव, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मुख्य अतिथि, प्रतिभागी वेंडरों तथा विभिन्न संगठनों से उपस्थित अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी दोहराया कि इस प्रकार के वेंडर मीट प्रापण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ एमएसई को सशक्त बनाने और एसजेवीएन के साथ उनकी सहभागिता को सुदृढ़ करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। वेंडर मीट के दौरान, सहभागी विक्रेताओं को उपलब्ध अवसरों तथा प्रापण प्रक्रियाओं से अवगत करवाने के लिए एसजेवीएन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब, जेम, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डीटीएक्स, एम1 एक्सचेंज, दलित इंडियन चौबेर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और महिला उद्यमी परिसंघ के प्रतिनिधियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। प्रस्तुति सत्र के पश्चात एसजेवीएन की ई-प्रापण प्रक्रिया, विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर पंजीकरण की प्रक्रिया तथा वेंडरों के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं सहायक उपायों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वार्ता सत्र आयोजित किए गए।

एलआईसी ने आईटी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया



मुंबई। भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई दूसरे इन्वेस्टर्स से अलग रास्ता अपनाया है। जहाँ कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल डिमांड में कमी के डर से आईटी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, वहीं एलआईसी ने इस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। कमजोर सेंटिमेंट के बावजूद प्ज एलोकेशन बढ़ा दिसंबर क्वार्टर के दौरान, एलआईसी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 3,136 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इसने एचसीएल टेक्नोलॉजीज में लगभग 2,293 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया और कोफोर्ज में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई। आईटी कंपनियों में

एलआईसी का कुल इन्वेस्टमेंट सिर्फ तीन महीनों में 1.82 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके पोर्टफोलियो में सेक्टर का शेयर 11.32 परसेंट से बढ़कर 12.43 परसेंट हो गया। यह ऐसे समय में हुआ है जब कई आईटी स्टॉक्स अपने हाल के हाई से 30 परसेंट तक गिर गए हैं। चिंता बनी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के आउटसोर्सिंग बिजनेस पर असर डाल सकता है। हालाँकि, एलआईसी का मानना है कि यह करेक्शन लंबे समय का मौका देता है। बवितहम में, एलआईसी की हिस्सेदारी सितंबर में 1 परसेंट से नीचे से दिसंबर तक बढ़कर 4.66 परसेंट हो गई, जबकि स्टॉक में तेजी से गिरावट आई थी। फाइनैशियल और मेटल में बिकवाली उसी समय, एलआईसी ने बैंकों और फाइनैशियल कंपनियों में अपना एक्सपोजर कम कर दिया। सबसे बड़ी बिक्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई, जहाँ उसने 3,080 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसने एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी

हिस्सेदारी कम की। कटौती के बाद भी, फाइनैशियल सर्विसेज 4.64 लाख करोड़ रुपए के साथ एलआईसी का सबसे बड़ा सेक्टर एक्सपोजर बना हुआ है। हालाँकि, तिमाही के दौरान पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा थोड़ा कम हुआ। एलआईसी ने लार्सन एंड टूब्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों में भी हिस्सेदारी कम की। मेटल में, इसने हिंडालको इंडस्ट्रीज और वेदांता में पोजीशन कम की। आईटी के अलावा चुनिंदा खरीदारी टेक्नोलॉजी के अलावा, एलआईसी ने सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज में 2,942 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसने एनएमडीसी, बजाज ऑटो और कोल इंडिया में भी होल्डिंग बढ़ाई। कुल मिलाकर, एलआईसी ने 73 एलएसई-लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और 90 दूसरी कंपनियों में अपना एक्सपोजर कम किया। इसके खरीदे गए स्टॉक्स में एवरेज प्राइस मूवमेंट कम होने से पता चलता है कि एलआईसी शॉर्ट-टर्म गेन के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही है।

सत्यन कुमार ओएनजीसी के बने डायरेक्टर (रणनीति एवं कॉर्पोरेट मामले)



नई दिल्ली। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने अनुसूची श्रेणियों के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) में निदेशक (रणनीति एवं कॉर्पोरेट मामले) के पद पर सत्यन कुमार तैनात हो गए हैं। यह फैसला पीईएसबी की बैठक के दौरान हुआ। चयन बैठक में कुल 12 उम्मीदवारों का

साक्षात्कार लिया गया। ये उम्मीदवार विभिन्न प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आए थे। सत्यन कुमार वर्तमान में ओएनजीसी की सहायक कंपनी ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। रणनीति और हरित ऊर्जा पहलों में उनके व्यापक अनुभव के कारण वे भारत की

सबसे बड़ी तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनी में निदेशक (रणनीति एवं कॉर्पोरेट मामले) के महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त हैं। पीईएसबी की सिफारिश को अब अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) को भेजा जाएगा। एसीसी की सहमति प्राप्त होने पर सत्यन कुमार ओएनजीसी के बोर्ड में निदेशक (रणनीति एवं कॉर्पोरेट मामले) के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निदेशक (रणनीति एवं कॉर्पोरेट मामले) ओएनजीसी की दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा, कॉर्पोरेट योजना और व्यवसाय विकास पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से जब कंपनी ऊर्जा परिवर्तन से गुजर रही है और नए ऊर्जा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है।

केन्द्रीय भंडारण निगम, भोपाल ने 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया



केन्द्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा 2 मार्च 2026 को 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती सूफिया फारुकी वली, भा.प्र. से. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम एवं श्री राम कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक के. भ.नि. द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। श्रीमती नेहा, उप महाप्रबंधक (सा.) द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। केन्द्रीय भंडारण निगम, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक नवरत्न सीपीएसई है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों सहित 700 से अधिक सूचीबद्ध वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समूचे भारत देश में विभिन्न नीतियों के सुचारु क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता

है। केन्द्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 51 केन्द्रीय भंडारगृहों के साथ विद्यमान हैं। के.भ.नि. द्वारा विगत कई वर्षों से उपार्जित स्कंधों का

विशेष छूट भी प्रदान की जाती है, जिससे कि किसानों द्वारा अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा शासकीय निजी संस्थानों/गोदामों एवं घरेलू



सुरक्षित वैज्ञानिक भंडारण किया जाता रहा है साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु सेवाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों द्वारा स्कन्ध भंडारण किए जाने पर भंडारण दर पर 30:

कीट नियंत्रण सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। श्री अविनाश खरात, उप महाप्रबंधक (सा.) द्वारा कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया।

विज्ञापन

आरईसी लिमिटेड इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में भविष्य के लिए तैयार इनोवेशन दिखाया



नई दिल्ली। आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट और एक्सपो 2026 में अहम भूमिका निभाई। पावर सेक्टर फाइनेंसिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर होने के नाते, आरईसी ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर तीन हाई-लेवल थीमैटिक सेशन होस्ट करेगा और अपने डेडिकेटेड पवेलियन में कटिंग-एज टेक्नोलॉजी को दिखाया।

वैश्विक चर्चा को आगे बढ़ाना तीन रणनीतिक सत्र

आरईसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी ट्रांजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के मेल पर बात करने के लिए तीन अलग-अलग सेशन बुलाए—एनर्जी के लिए AI पर ग्लोबल मिशन (16 फरवरी - 16:30 से 17:25 बजे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के साथ पार्टनरशिप में, यह सेशन AI&रेडी और सिटिजन-रेडी पावर सिस्टम बनाने पर फोकस करता है। इसका मकसद लीडरशिप को हाई-इम्पैक्ट यूज केस पर एक साथ लाना है, जिससे क्लीन बिजली ज्यादा सस्ती और सबको साथ लेकर चलने वाली बन सके। AI

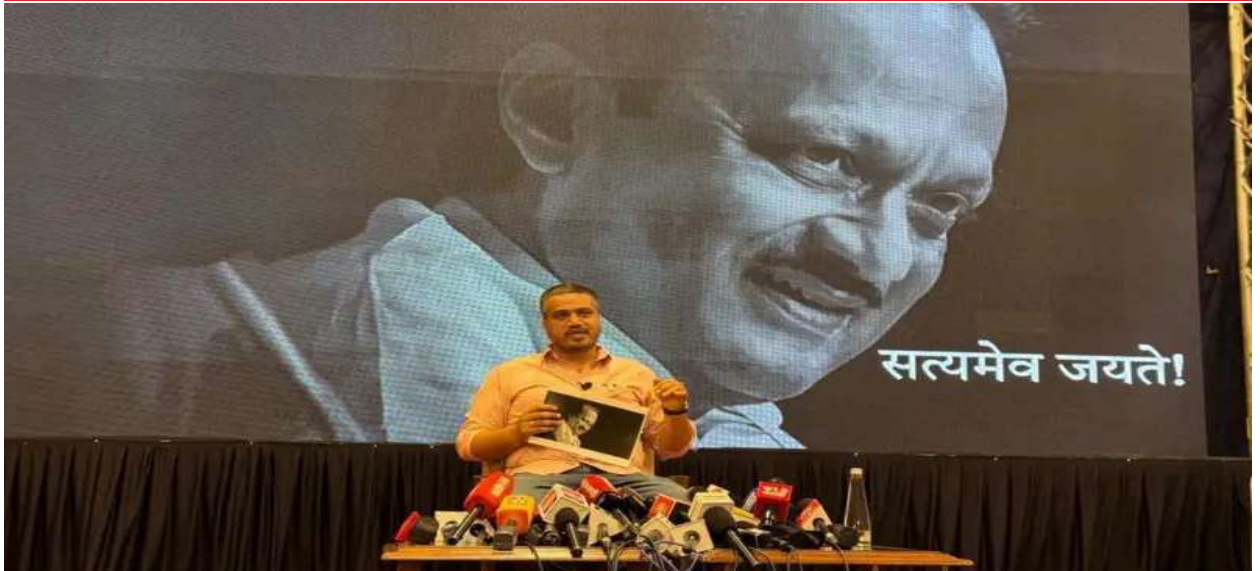
एनर्जी-फाइनेंस ट्राइफेक्टा (17 फरवरी - सुबह 10:30 से 11:25 बजे, कमरा नंबर 10): वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, आरईसी एनर्जी-इंटेंसिव डेटा सेंटर्स के तेजी से विस्तार की की। चर्चा भारत में AI ड्रिवन एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और मजबूत, ग्रीन डेटा-सेंटर डेवलपमेंट को अनलॉक करने के लिए जरूरी पॉलिसी और फाइनेंसिंग फाउंडेशन पर फोकस करेगी।—इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) और एआई रेडी पावर सेक्टर (18 फरवरी दृ 11:30 से 12:25, वेस्ट विंग रूम 4 I): एफएसआर ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप में, यह सेशन पावर सेक्टर के लिए एक कॉमन, इंटरऑपरेबल डिजिटल लेयर के तौर पर इंडिया एनर्जी स्टैक को एक्सप्लोर करता है। चर्चा इस बात पर सेंटर होगी कि यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन कॉस्ट को कैसे कम कर सकता है और कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी एक्सेस से एनर्जी एजेंसी में बदलाव को कैसे इनेबल कर सकता है। कंज्यूमर्स को मजबूत बनाना पीयर-टू-पीयर (P2P) एनर्जी ट्रेडिंग की हुई लांचिंग। इस समिट का एक बड़ा हाईलाइट इंडिया एनर्जी स्टैक सेशन के दौरान पीयर-टू-पीयर (P2P) एनर्जी ट्रेडिंग प्रोग्राम का लॉन्च किया गया। यह इनिशिएटिव कंज्यूमर्स को

बिजली के पैसिव रिसीवर से एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। सिक्थोर, इंटरऑपरेबल डिजिटल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, P2P ट्रेडिंग पड़ोसियों को आपस में सीधे सरप्लस सोलर एनर्जी खरीदने और बेचने की इजाजत देगी, जिससे एक डीसेंट्रलाइज्ड एनर्जी इकोसिस्टम बनेगा और घरों और छोटे बिजनेस के लिए मोनेटाइजेशन के नए मौके मिलेंगे।

इनोवेशन का हब: आरईसी पवेलियन

आरईसी लिमिटेड अपने 140 sq m के पवेलियन में डिजिटल-फर्स्ट एनर्जी लैंडस्केप के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया, जो फर्स्ट फ्लोर, हॉल 4 (4F-19) में है। विजिटर अलग-अलग एआई ड्रिवन सॉल्यूशन देख सकते थे, जिन्हें ग्रिड एफिशिएंसी बढ़ाने, यूटिलिटी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और भारत को एक स्मार्ट, ग्रीन एनर्जी पयूचर की ओर ले जाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन कोशिशों के जरिए, REC लिमिटेड एक सस्टेनेबल और डिजिटली मजबूत भारत को पावर देने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने में सबसे आगे है।

अजित पवार विमान हादसा : भतीजे रोहित पवार ने लगाया साजिश का आरोप



राजकुमार केशरवानी महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान हादसे में मौत के बाद 10 फरवरी को एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चाओं का एक नया दौर शुरू हो गया है। इसकी वजह अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार की ओर से लगाए गए नए आरोप हैं। रोहित पवार ने अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु में साजिश की आशंका जताई है। रोहित पवार ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें एयरलाइन कंपनी वीएसआर, बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर पर संदेह है। रोहित पवार ने कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी इसलिए जुटानी पड़ी क्योंकि जांच एजेंसियां बहुत धीमी गति से काम कर रही थीं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि डीजीसीए और सरकार के खिलाफ उनका कोई आरोप नहीं है। रोहित पवार ने कहा कि मैंने, मेरी टीम और मेरे दोस्तों ने उन लोगों की मदद से यह जानकारी जुटाई जिनसे हम संपर्क कर सके। यह जानकारी हमें कहां से मिली, इसका जवाब अजितदादा से मिले भरोसे और प्यार में है। अगर हर संभव तरीके से जांच की जाए, तो सच्चाई सामने आ सकती है। 28 जनवरी को अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसी दिन एयरलाइन वीएसआर के मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा था कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और पायलट अनुभवी था।

वीएसआर कंपनी के मालिक के दावे

36 **प्राइम स्पेक्टोर (मासिक पत्रिका) मार्च 2026, दिल्ली**

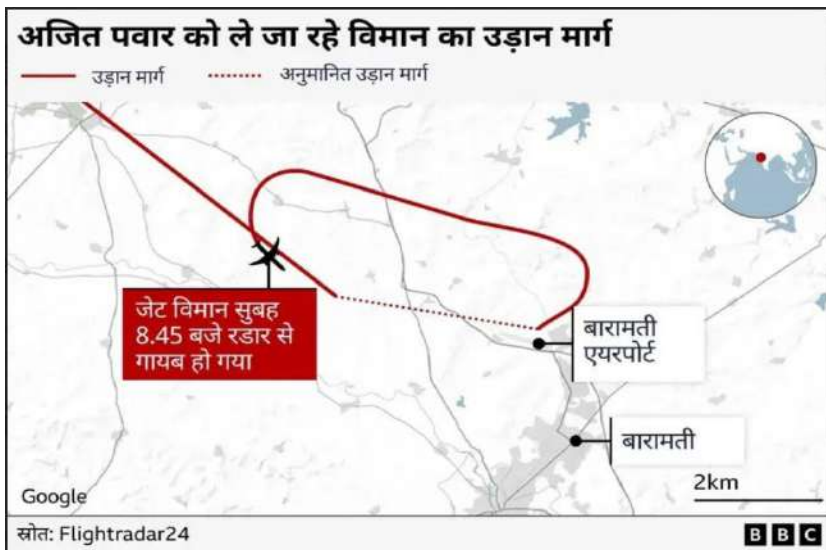
पर सवाल

रोहित पवार ने कहा कि इसी कंपनी के एक विमान का 2023 में मुंबई में भी हादसा हुआ था। उस दुर्घटना में छह यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय भारी बारिश और कम दृश्यता को विमान के रनवे से फिसलने की वजह बताया गया था। इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। उनका कहना था कि अगर यह रिपोर्ट सामने आती और उस पर कार्रवाई होती, तो अजित पवार की दुर्घटना को टाला जा सकता था। रोहित पवार ने कहा कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। उनके मुताबिक, एजेंसी ने लेवल-1 की खामियों का हवाला देते हुए वीएसआर का लाइसेंस रद्द कर दिया था। रोहित पवार ने सवाल किया कि अगर ऐसा है, तो वीएसआर के विमान अब भी कैसे उड़ रहे हैं और उन्हें उड़ान की अनुमति क्यों दी जा रही है। 28 जनवरी को, अजित पवार के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ घंटों बाद, जब दिल्ली में पत्रकारों ने वीएसआर कंपनी के मालिक विजय कुमार सिंह से 2023 की घटना के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था, 2023 में जो हुआ, वह बारिश और कम दृश्यता की वजह से हुआ था।

विमान कंपनी पर आरोप

रोहित पवार ने दावा किया कि उन्होंने वीएसआर में काम कर चुके पूर्व पायलटों, इंजीनियरों और कुछ पूर्व डीजीसीए अधिकारियों से बातचीत की है। रोहित पवार

ने कहा कि नियमों के अनुसार पायलटों को उड़ान के बाद तय समय का आराम मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी इसका पालन नहीं कर रही और उड़ान घंटों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विमान में लगा कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर कई बार बंद रखा जाता है और अलग-अलग उड़ानों के बीच अपनाई जाने वाली चेकलिस्ट के लिए कोई ठोस प्रणाली नहीं है। रोहित पवार ने यह भी कहा कि कंपनी विमानों के रखरखाव में लापरवाही बरत रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विमान पहली बार में लैंड नहीं कर पाया, तो उसने दोबारा कोशिश की। लेकिन क्या दूसरी बार भी रनवे साफ दिख रहा था, या पायलट को कहीं और जाने से रोका गया क्योंकि कंपनी ईंधन बचाना चाहती थी। रोहित पवार ने कहा कि अगर विमान किसी दूसरे हवाई अड्डे पर उतरता, तो पहले से बुक किया गया लगभग 10 लाख रुपये का किराया बेकार हो जाता। तो क्या इसी वजह से कम दृश्यता के बावजूद विमान को यहां उतारने की कोशिश की गई। उन्होंने इस आरोप के संदर्भ में बीमा कंपनी की संभावित कार्रवाई का भी जिक्र किया। रोहित पवार ने कहा कि विमान में एक स्टॉल वार्निंग सिस्टम होता है, जो विमान की गति कम होने पर चेतावनी देता है। लेकिन हमारे पास जानकारी है कि अजितदादा जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, उसमें यह सिस्टम बंद था। कुछ लोगों ने हमें यह जानकारी दी, लेकिन उन्होंने नाम न बताने को कहा क्योंकि उनकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। रोहित पवार



ने यह भी सवाल उठाया कि वीएसआर कंपनी अपने विमानों का रखरखाव खुद कर रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए कंपनी के पास जरूरी विशेषज्ञ थे और क्या उनके पास इसके लिए अनुमति थी। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से जानकारी जुटानी पड़ रही है क्योंकि जांच आगे नहीं बढ़ रही है।

ईंधन बम को लेकर आरोप

रोहित पवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि वीएसआर कंपनी पैसे बचाने के लिए विमानों में अतिरिक्त ईंधन डिब्बों में भरकर ले जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। रोहित पवार ने कहा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक, बारामती में हुए हादसे के दौरान चार से पांच धमाकों की आवाज सुनी गई थी। क्या उस दिन विमान में अतिरिक्त ईंधन था और क्या ये डिब्बे उस हिस्से में रखे गए थे जहां अजितदादा बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ईंधन मौजूद था, तो वह एक तरह का बम बन सकता है। रोहित पवार ने कहा कि आज भी कई वीआईपी इन कंपनियों के विमानों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन

मामलों में कार्रवाई जरूरी है।

बुकिंग कंपनी एरो पर आरोप

रोहित पवार ने वीवीआईपी फ्लाइट बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बुकिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की जाती थी, जिसमें कंपनी का हैंडलर, कंपनी का मालिक, वीवीआईपी लोगों के पीए और महाराष्ट्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के निदेशक शामिल थे। रोहित पवार ने इस ग्रुप की चोट के कथित स्क्रीनशॉट भी दिखाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस हैंडलर के पास वीआईपी यात्रियों की पूरी जानकारी थी, वह कौन था।

उड़ान के समय में बदलाव पर सवाल

रोहित पवार ने कहा कि विमान का निर्धारित प्रस्थान समय सुबह 7 बजे था, लेकिन वह 8।10 बजे क्यों रवाना हुआ। उन्होंने पूछा कि उड़ान का समय क्यों बदला गया और देरी की जिम्मेदारी किसकी थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिरी समय में पायलट क्यों बदले गए। रोहित पवार ने कहा कि पहले ईमेल में पायलट साहिल मदन और सह-पायलट यश के नाम थे, लेकिन अगले

दिन पायलट सुमित कपूर और सह-पायलट शांभवी पाठक के नाम सामने आए। उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक, मुख्य पायलट को उड़ान से कम से कम 20 मिनट पहले और सह-पायलट को 35 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। उन्होंने पूछा कि सुबह 6.30 बजे ट्रैफिक कैसे था, पायलट कहां ठहरे थे और वे किस रास्ते से आ रहे थे। रोहित पवार ने कहा कि विमान की गति को देखते हुए हर सेकंड अहम है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और बारामती एटीसी की रिपोर्टों में समय को लेकर अंतर है। उन्होंने आग की लपटें दिखने के समय और पायलट की आखिरी आवाज के समय को लेकर भी सवाल उठाए।

रनवे 11 को लेकर सवाल

रोहित पवार ने कहा कि बारामती हवाई अड्डे पर रनवे 11 और रनवे 29 दोनों उपलब्ध थे। रनवे 29 टेबल टॉप नहीं था, फिर भी रनवे 11 पर उतरने की जिद क्यों की गई, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। विमान दुर्घटना के कुछ घंटों बाद वीएसआर के मालिकों ने क्या जानकारी दी? दुर्घटना के कुछ घंटों बाद, दिल्ली में पत्रकारों ने बात करते हुए वीएसआर वेंचर के के मालिक विजय कुमार सिंह ने बयान दिया था। उस समय विजय कुमार सिंह ने कहा था, पायलट ने विमान को रनवे 29 पर उतारने की कोशिश की थी। लेकिन वहां विमान को उतारना संभव नहीं था। इसलिए उसने रनवे 11 पर दोबारा उतारने का प्रयास किया। मुझे अभी तक यही जानकारी मिली है। उन्होंने कहा था कि हम इस घटना से बेहद दुखी हैं। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मुख्य रूप से, यह घटना इसलिए घटी क्योंकि पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। रनवे दिखाई न देने पर पायलट विमान को लैंड नहीं करते। इस विमान का पायलट बहुत अनुभवी था। उसे 16 हजार घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। इसके अलावा, सह-पायलट को भी 1500 घंटे का उड़ान अनुभव था। पायलट सहारा, जेटलाइट और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस में भी काम कर चुके थे। विमान की स्थिति के बारे में बात करते हुए विजय कुमार सिंह ने कहा था कि विमान का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया गया था। विमान में कोई समस्या नहीं थी। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। रोहित पवार ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कराई जाए। उन्होंने कहा कि केवल डीजीसीए के अंतर्गत आने वाले संगठनों से जांच होने पर संदेह बना रह सकता है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की एजेंसियों के नाम सुझाए।



किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है सरकार : डॉ. मोहन यादव



श्वेतांक वर्मा मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं, ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी गत वर्षों के तरह बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपये प्रति

क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प-पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। आगामी वर्षों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर उससे भी आगे निकलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित बैठक में व्यक्त किए। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्री नीरज मंडलोई सहित कृषि, राजस्व, सहकारिता, जल संसाधन, उद्यानिकी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश, देश का फूड बास्केट है, जहां दलहन, तिलहन और सब्जी उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है। हमारे राज्य

के किसान आगे बढ़ें और समृद्ध हों, इसके लिए सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है। कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई सामने आई है। इसे ध्यान में रखकर गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, इससे रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों के हित में प्राप्त सुझावों पर भी राज्य सरकार विचार करेगी। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा राशि बढ़ाने, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान पर मुआवजे, मंडी अधिनियम के प्रावधानों, फसल गिरदावरी, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने, विद्युत प्रदाय और सिंचाई व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने मध्यप्रदेश की जल संचय की पहल को सराहा



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। देश की कई महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल होने के साथ ही प्रदेश में 250 से अधिक नदियां हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन के लिए देश में आरंभ हुआ जल संचय जन भागीदारी अभियान सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। मध्यप्रदेश ने इस अभियान के प्रथम चरण में 2 लाख 79 हजार जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर महत्वपूर्ण

योगदान दिया है। द्वितीय चरण में भी मध्यप्रदेश में 64 हजार 395 कार्य प्रगति पर हैं और 72 हजार 647 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस प्रकार 1 लाख 37 हजार 42 संरचनाओं के साथ प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गुरुवार को आयोजित संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस को मंत्रालय भोपाल से संबोधित कर रहे थे। जल संचय-जन भागीदारी की व्यापक समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर.

पाटिल, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर शामिल हुए। केन्द्रीय मंत्री पाटिल ने अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सामुदायिक सहभागिता पर आधारित जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में देश के सम्मुख श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भूजल स्रोतों के दोहन के कारण गिरते हुए भूजल स्तर, प्राचीन जल संग्रहण संरचनाओं के क्षरण और नदियों के कम होते प्रवाह के प्रति हम पूर्णतः सजग हैं। इसलिए मध्यप्रदेश ने जल संचय-जन भागीदारी की राष्ट्रीय पहल को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आत्मसात करते हुए राज्य स्तर पर इसे व्यापक जनभागीदारी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से जिन नदियों का उद्गम है, उनके जल का स्रोत प्रदेश के वन हैं। यह नदियां अन्य राज्यों की कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

एमपी बांधों की संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर-सीआर पाटिल



केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल ने कहा कि मध्यप्रदेश बांधों की संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश गुजरात को पानी दे रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के

माध्यम से उत्तर प्रदेश को भी पानी मिलेगा। इस परियोजना से 10 लाख 62 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। राजस्थान के साथ भी पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सकारात्मक सोच दिखाई है। मध्यप्रदेश, देश के सर्वाधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने वाला राज्य है। केन्द्रीय मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि

मध्यप्रदेश ने जल संचय जनभागीदारी अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारी कोशिश है कि गांव का पानी गांव और खेत का पानी खेत में सिंचाई के लिए उपयोग हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से पेयजल की बर्बादी रोकने का भी आह्वान किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि मध्यप्रदेश एक बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य है। बैठक के दौरान खंडवा (पूर्व निमाड़), राजगढ़ और इंदौर जिलों के जिला कलेक्टरों ने विस्तृत प्रस्तुतियां दीं, जिनमें जल संचय जनभागीदारी 2.0 के क्रियान्वयन की जिला स्तरीय प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

पुण्य तिथि पर विशेष

सच को मुकम्मल जीने वाले पांडे बेचन शर्मा उग्र



राजीव कुमार ओझा
जाने-माने पत्रकार

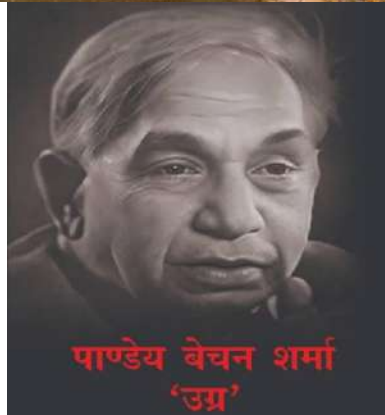
चुनार तहसील के जलालपुर माफी के मूल निवासी बैजनाथ पांडे के चुनार तहसील मुख्यालय के समीपस्थ सहपुर मुहल्ले की बभनटोली के घर में श्रीमती जयकली की कोख से 29 दिसंबर 1900 ' को जिस बालक का जन्म हुआ ,एक टोटके के तहत जिस नवजात शिशु को काल का ग्रास बनने से बचाने के लिए बिना मोल बेचने का स्वांग रचा गया,जिसका नाम बेचन रखा गया वह भविष्य में कालजयी साहित्यकार पांडे बेचन शर्मा उग्र होगा, साहित्य के वैश्विक क्षितिज का चमकता सितारा होगा ,चुनार का नाम रोशन करेगा यजमानी वृत्ति से मुफलिसी में जी रहे बालक बेचन के पिता बैजनाथ पांडे और माता जयकली ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। मैं हाई स्कूल का छात्र था जब मैंने पांडे बेचन शर्मा उग्र की कालजयी कृति ८ अपनी खबर ८ पढ़ी थी। पी.डी.एन.डी. इंटर कालेज चुनार के विद्वान शिक्षकों सर्वश्री सच्चिदानंद तिवारी जी, दत्तात्रेय पांडेय जी ,राम प्यारे मिश्रा जी मेरी साहित्यिक अभिरुचि को सराहते थे,प्रोत्साहित करते थे। मैं उनसे एक जिज्ञासु छात्र की तरह चुनार की धरती के कलमकार पांडे बेचन शर्मा उग्र के व्यक्तित्व,कृतित्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कालजयी कृति – अपनी खबर पढ़ने के बाद मुझे गर्वानुभूति हुई कि मैं उस धरती पर पला, बढ़ा जिस धरती ने हिन्दी साहित्य को ऐसा कलमकार दिया जो सच जीता था, सच लिखता था। जिसकी लौह लेखनी की तपिश ब्रिटिश हुकूमत को इस कदर बेचौन करती थी, इस कदर खौफजदा करती थी की ब्रिटिश हुकूमत को उनकी कृतियों को प्रतिबद्धित करना पड़ता था। आज के कलमकारों, पत्रकारों को उग्र को पढ़ना चाहिए। अपने उपन्यास – कढ़ी में कोयला में उग्र ने एक पात्र के प्रश्न और उत्तर के जरिए जो बताया है पत्रकारों को उसके आलोक में अपना चेहरा देखना चाहिए – अखबार नबीसी का आदर्श



क्या होना चाहिए?

इस प्रश्न का उग्र जी का जबाब काबिले गौर है। जनसेवा , सज्जन सत्कार और दुर्जन सुधार। असिल अखबारनवीस न्याय और व्यवस्था का सिपाही है। उसमे और पुलिस में महज इतना ही फर्क है कि पुलिस तनखाह लेकर जनसेवा करती

है और पत्रकार अमूल्य सेवा करता है। मेरे मते असिल पुलिस अखबारनवीस है,न की कोतवाली वाले। पत्रकार भारतीय संत परम्परा का नवयुगीन संस्करण है अगर वह अपना कर्तव्य जानता है। उग्र दैनिक में उन्होंने स्पष्ट लिखा है – हम अखबार की ड्यूटी यह मानते हैं कि जनता की जानकारी के लिए विविध वादों को उनके सामने पेश करने के बाद ईमानदारी से विवेक के कपड़े में छानकर शुद्ध कल्याणकारी रस उसके गले के नीचे उतारें। वह ऐसे कलमकार थे जो लेखन के धरातल पर मुकम्मल ईमानदार थे। जिन्होंने लिखते समय अपनी पारिवारिक मुफलिसी ,अपने सहोदर भाइयों के कुसंस्कार को भी उद्घाटित किया और ऊँची नाक वाले स्वजातियों के किरदार से शराफत का नकाब उतारने में भी संकोच नहीं किया। खुद को भी नहीं बख्शा। अपनी आत्मकथा मे उन्होंने लिखा— अक्षरारंभ



पाण्डेय बेचन शर्मा
'उग्र'

से पहले ही मेरे कान में वेश्या या रन्डी शब्द पड़ चुका था। मैं पांच ही छः साल का रहा होऊंगा जब मेरे घर में मिर्जापुर की एक टकैल वेश्या का प्रवेश हुआ था। पुरुष वेश में चूड़ीदार चपकन और पगड़ी पहनकर वह बाहर वाली कोठरी में रात में आई और तब तक रही जब तक मेरे चाचाजी होंथ में खड़ाऊं लेकर उसे मारने को झपटे

नहीं ,यथयोग्य दुर्वचन सुनाते हुए। मुहल्ले के आधे दर्जन मनचले युवक उस वेश्या से मिलने मेरे यहां आ जमते थे। मकान के अंदर की ब्राह्मणियाँ मेरी मां और भाभी किंकर्तव्यविमूढ़ा हो गई थीं। भाभी तो रोने भी लगी थी। पर ये कुलीन औरतें मुखर विरोध करने में असमर्थ थीं, इसलिए कि मेरे उन्मत्त भाई साहब एक ही लाठी से दोनों ही को हांकने में कोई ग्लानि या हानि नहीं समझते थे। (जिज्ञासु पाठक उनकी कालजयी कृति अपनी खबर पढ़ सकते हैं जो चौखम्मा प्रकाशन चौक वाराणसी ,विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी से प्राप्त हो सकती है।) स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान देने वाले आज के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिवप्रसाद गुप्त जी, आज के यशस्वी संपादक बाबूराव विष्णु राव पराडकर जी ने बेचन पांडे नामक अनगढ़ किरदार को तराशकर उग्र बनाने में जिस

उदारता का परिचय दिया, संभल दिया उसने बेचन पांडे को तराश कर पांडे बेचन शर्मा उग्र बनाया। बनारस से 1920 में शुरू हुआ आज अखबार कलमकार उग्र की प्रथम पाठशाला रहा इसे उग्र जी ने अपनी आत्मकथा में उद्धृत किया है। बेचन पांडे के उग्र होने का प्रारम्भ हुआ प्रताप की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता से। जिसमें प्रतिभाग करते समय अपनी कविता में बेचन पांडे ने अपने नाम के साथ पहली बार उग्र जोड़ा था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा। अभिनय के क्षेत्र में भी योगदान दिया, पत्रकारिता, संपादन क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वह बिना डरे, बिना झुके अपनी लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग उगलते रहे, स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे। अपने अखड़ स्वभाव की वजह से उग्र अपने समकालीन साहित्यिक मठाधीशों के निशाने पर रहे। प्रसंगवश उनकी कालजयी कृति चॉकलेट की चर्चा का लोभ संवरण नहीं कर सकता। उस दौर में समलैंगिक रिश्तों के काले पक्ष को उद्घाटित करने का साहस उग्र जी ने अपनी खबर में रामलीला मंडली के एक महंत की बटुक बिलासिता को उजागर कर दिया है। चॉकलेट जैसी उनकी कृति को अश्लील बताते हुए उनके समकालीन साहित्यिक मठाधीशों ने वितंडा खड़ा किया, चॉकलेट के खिलाफ घासलेट अभियान छेड़ा गया, जिसका नेतृत्व विशाल भारत के संपादक पं. बनारसी दास चतुर्वेदी कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी तक यह विवाद पहुंचाया। तथाकथित अश्लीलता का राग अलापने वाले साहित्यकारों के अगुआ को महात्मा गांधी ने दो टूक जबाब दिया था की मुझे इस पुस्तक में कहीं कोई अश्लीलता नजर नहीं आई। दरअसल चॉकलेट के माध्यम से उग्र जी ने अभिभावकों और स्कूली छात्रों को समलैंगिक गुरुओं की अप्राकृतिक यौन लिप्सा से आगाह किया था। चॉकलेट में उन्होंने लिखा – शिक्षण संस्थाओं, बाल संस्थाओं में शिक्षक पद पर नियुक्त लोग डूब कर मछली निगलने वाले हैं जो सत्तर चूहे खाकर दूसरों को हज की शिक्षा देते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने बांटो और राज करो की विभाजनकारी कुत्सित नीति के तहत हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक नफरत की जो खाई खोदी थी उसके खिलाफ अपनी कृतियों में उग्र जी ने बेबाकी से लिखा। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे जब लिखे गए थे। अपनी कहानी ईश्वरद्रोही में उग्र एक पात्र से कहते हैं, मौलवी साहब! मेरी नजर में मजहब की उतनी ही इज्जत है जितनी पोशाकों की। लुंगी लगाने वाला धोती पहनने वाले को काफिर नहीं कह सकता।

पगड़ी पहनने वाला तुर्की टोपी पहनने वाले को म्लेच्छ नहीं कह सकता। अपनी अपनी पसंद है, आप दीन इस्लाम को मानते हैं लुंगी पहनिए, राम हिन्दू है धोती पहने। मैं कुछ नहीं हूँ, आदमी हूँ जो जी में आए पहनूँगा। पोशाकों के लिए लड़ना मुसलमानपन नहीं, हिन्दूपन भी नहीं, गंधापन है। खुदा राम और चंद हसीनों के खतूत में उग्र लिखते हैं – संसार के सारे पापों के जिम्मेदार वे नहीं हैं जो अत्याचार या व्यभिचार करते हैं बल्कि वे हैं जो अत्याचारों और व्यभिचारों को सहते हैं। इन दो उद्धरणों के आलोक में उग्र की वैचारिक उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। उग्र जी साहित्यानुरागी महादेव सेठ के मतवाला प्रेस में सेवारत थे। उनके अभिन्न सखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मतवाला प्रेस में सेवारत थे। महादेव सेठ से जुड़ा उग्र जी का एक संस्मरण इस बात की तस्दीक करता है की वह सच लिखते भी थे और सच जीते भी थे। कलकत्ता के एक प्रकाशक व्यापारिक सिलसिले में महादेव सेठ से मिलने आए थे। किसी बात पर उन्होंने निराला जी पर प्रहार कर दिया। सीधे सादे निराला जी अपमान का यह घूँट पीकर सकते में आ गए लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। उग्र जी ने निराला जी के आत्मसम्मान को जगाया परिणाम यह हुआ की जब कलकत्ता के प्रकाशक मतवाला प्रेस से निकले निराला जी ने उनसे प्रहार का हिसाब बराबर कर लिया। पिनपिनाता हुआ प्रकाशक उलटे पाँव मतवाला प्रेस लौटा और निराला जी की शिकायत की। महादेव सेठ ने निराला जी को बोरिया बिस्तर समेट कर मतवाला प्रेस से रुखसत होने का फरमान सुनाया तो उग्र जी ने प्रतिरोध करते हुए कहा की ५ निराला ने जो किया मेरे उकसावे पर किया इसलिए बोरिया बिस्तर मेरा भी बंधेगा। ऐसे थे पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र उन गिने चुने भारतीय साहित्यकारों में शामिल हैं जिनके साहित्यिक अवदान, कृतियों, व्यक्तित्व पर देश के अलावा विदेशों में भी शोध किया गया। दुर्भाग्यवश उग्र जी का साहित्य समग्र रूप से आज भी उपलब्ध नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी और आदर्श पुस्तकालय खोजवां वाराणसी में उनकी कृतियाँ उपलब्ध हैं। उग्र जी ने काफी कुछ छद्म नामों से भी लिखा लेकिन वह सहज सुलभ नहीं हैं। गांधी आश्रम शीर्षक से प्रकाशित उग्र जी की पहली कहानी शशि मोहन के छद्म नाम से प्रकाशित हुई थी। उनका कोई वारिस न होने की वजह से भी उनकी कृतियाँ व्यवस्थित और समग्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं –

01- अपनी खबर (आत्म कथा)

02 –चंद हसीनों के खतूत , खुदा राम, फागुन के दिल्ली का दलाल ,बुधुआ की बेटी ,शराबी

,घंटा ,सरकार तुम्हारी आँखों में ,कढ़ी में कोयला ,जी जी जी,फागुन के दिन चार ,जुहू, चॉकलेट, जब सारा आलम सोता है ,सब्जबाग ,गंगा माता,मनुष्यान्द (सभी उपन्यास)।

03 –प्रमुख कहानी कहानी संकलन –

सोसाइटी ऑफ डेविल्स, चिंगारिया, बलात्कार निर्लज्जा, दोजख की आग, रेशमी, पंजाब की महारानी, सनकी अमीर, कला का पुरस्कार, जब सारा आलम सोता है, पोली इमारत, चित्र विचित्र

यह कंचन सी काया, काल कोठरी, ऐसी होली खेलो लाल, मुक्ता।

04 –महात्मा ईशा, चुम्बन ,गंगा का बेटा , डिक्टेटर आवारा ,अन्नदाता माधव महाराज महान ,नई पीढ़ी (सभी नाटक)।

05 –लाल क्रांति के पंजे में ,चार बेचारे, उजबक (सभी एकांकी)।

06 –व्यक्तिगत (संस्मरण)

07 –फाइल प्रोफाइल (खतो किताबत साहित्य)

08 –गालिब –उग्र (टीका)

09 –ध्रुवचरित (काव्य कृति)

संपादन – हस्त लिखित अखबार उग्र ,आज , विश्वमित्र ,स्वदेश(दशहरा विशेषांक) , ,वीणा ,स्वराज्य ,भूत (हास्य व्यंग्य पत्र) मतवाला ,संग्राम ,विक्रम ,हिन्दी पंच, उग्र (मासिक पत्रिका)

कालजयी साहित्यकार पांडे बेचन शर्मा उग्र ने 23 मार्च 1967 को जमुनापार कृष्ण नगर दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम सांस ली।

‘उग्र जी की जन्म तिथि को लेकर मतैक्य का अभाव है। उनकी जयंती 24 दिसंबर को मनाई जाती है ,इससे असहमत लोग दावा करते हैं की उग्र जी की वास्तविक जन्म तिथि 29 दिसंबर 1900 है। बकौल उग्र ५ विक्रमीय संवत के १९५७ वे वर्ष के पौष शुक्ल अष्टमी की रात साढ़े आठ बजे मेरा जन्म यूपी के मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के सहूपुर नामक मुहल्ले में बैजनाथ पांडे नमक कौशिक गोत्रोत्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण के घर पर हुआ।’ स्वदेश के 1924 में प्रकाशित विजया विशेषांक के अतिथि संपादक पांडे बेचन शर्मा उग्र ने इस विशेषांक में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रप्रेम की ऐसी आग भरी की विशेषांक जब्त हुआ ,अखबार बंद हुआ , अखबार के स्वामी संपादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग कायम हुआ। उनको 27 महीने कृष्ण जन्म भूमि (जेल)में गुजारना पड़ा।

नोट-लेखक राजीव कुमार ओझा, पूर्वांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और देश के राजनी- तिक विश्लेषण में पारखी नजर रखते हैं।

हरिद्वार में भव्य कुंभ मेले की तैयारी, केंद्र सरकार ने मंजूर किए 500 करोड़ रुपए



सुनील नेगी

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भव्य रूप से कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली पर्व को मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के साथ देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकास कर रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ मेला बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने तैयारी के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी है। राज्य प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, और जिला अधिकारी सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 7 मार्च को उत्तराखंड की भूमि पर पधार रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अच्छा मेला आयोजित होगा। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को

निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण ढंग से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने, यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन को व्यवस्थित करने तथा कार्यक्रम स्थलों पर स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने समेत किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। धामी ने कहा कि मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को जोड़ता है और एक-दूसरे के बीच प्यार और रिश्ते को मजबूत करता है। होली के इस शुभ अवसर पर हम राज्य के विकास

के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं। एक्स पोस्ट में धामी ने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को धर्म की अधर्म और भक्ति की अहंकार पर विजय के पावन प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए, इस पावन अवसर पर हम सभी अपने जीवन से नकारात्मकता, अहंकार और बुराइयों का त्याग कर प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का संकल्प लें।

कुंभ मेला-2027 मेला क्षेत्र में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए 50-27 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर भवन निर्माण के लिए 50.27 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 102 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी। ऊधमसिंह नगर जिले के उपजिला चिकित्सालय बाजपुर में चिकित्साधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के चार करोड़ की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर भवन निर्माण के लिए 50.27 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है।





उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भव्य रूप से कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली पर्व को मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के साथ देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकास कर रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ मेला बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने तैयारी के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी दी है। राज्य प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, और जिला अधिकारी सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 7 मार्च को उत्तराखंड की भूमि पर पधार रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अच्छा मेला आयोजित होगा। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण ढंग से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने, यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन को व्यवस्थित करने तथा कार्यक्रम स्थलों पर स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने समेत किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। धामी ने कहा कि मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को जोड़ता है और एक-दूसरे के बीच प्यार और रिश्ते को मजबूत करता है। होली के इस शुभ अवसर पर हम राज्य के विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं। एक्स पोस्ट में धामी ने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को धर्म की अधर्म और भक्ति की अहंकार पर विजय के पावन प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए, इस पावन अवसर पर

हम सभी अपने जीवन से नकारात्मकता, अहंकार और बुराइयों का त्याग कर प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का संकल्प लें।

पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए करोड़ों की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर भवन निर्माण के लिए 50.27 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 102 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी। ऊधमसिंह नगर जिले के उपजिला चिकित्सालय बाजपुर में चिकित्साधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के चार करोड़ की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर भवन निर्माण के लिए 50.27 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा हर की पैड़ी से ललतारों सेतु तक गलियों का सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 9 करोड़, लक्सर के स्थान पर स्मार्ट सिटी पीआईड्यू की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत विधानसभा क्षेत्र खानपुर में नारसन हरजौली जट मुडलानालंडौराजौरासी बुद्धाहेडी बजेडी-राजपुताना सड़क पर आरसीसी पुल व क्षतिग्रस्त एप्रोच का सुरक्षात्मक कार्य के लिए पहली किस्त में 2.67 करोड़, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति दी। चंपावत तहसील के तहत पूर्णागिरी में हुड्डी नदी की बाढ़ से ग्राम छानीगोट की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य के लिए 2.30 करोड़, चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में रामगंगा नदी तट पर हो रहे भू-कटाव एवं आवासीय भवनों के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के लिए 2.74 करोड़, विकासखंड भटवाडी के ग्राम हर्षिल में भागीरथी नदी किनारे आवासीय एवं अनावासीय भवनों के सुरक्षात्मक कार्य के लिए 4.10 करोड़, धर्मपुर विधानसभा में नगर निगम क्षेत्र के तहत सुसवा नदी के दोनों तटों पर दूधा

देवी पुल के डाउनस्ट्रीम में बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 1.72 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा नगर पंचायत ईमलीखेड़ा की लीगेसी वेस्ट का निपटारा करने को 13.90 लाख, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोबरियासा, रिखणीखाल का नाम शहीद अनुज नेगी के नाम पर रखने की स्वीकृति दी।

12 साल में आयोजित होता है कुंभ

हरिद्वार में कुंभ मेला हर 12 साल में हरिद्वार, भारत में आयोजित होने वाला एक मेला है। सटीक तिथि हिंदू ज्योतिष के अनुसार निर्धारित की जाती है। मेला तब आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इस घटना का हिंदुओं के साथ-साथ अन्य आध्यात्मिक साधकों के लिए गहरा धार्मिक महत्व है। ऐतिहासिक रूप से, यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक आयोजन था और इसमें अरब तक के व्यापारी शामिल होते थे। कोविड-19 महामारी के बीच हरिद्वार कुंभ मेला वर्ष 2021 में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ था। एक अर्ध कुंभ मेला कुंभ मेले के छह साल बाद आयोजित किया जाता है। आखिरी अर्ध कुंभ मेला 2016 में हुआ था। उत्तराखंड का हरिद्वार विश्व भर में हिंदू श्रद्धालुओं के सबसे बड़े जमावड़ों में से एक के आयोजन का अवसर प्रदान करता है। गंगा नदी की उपस्थिति से ध्यान, हरिद्वार और इसके घाट क्रमशः हर तीन, छह और बारह वर्षों में लोकप्रिय कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और महा कुंभ मेला आयोजित करने के लिए सौभाग्यशाली हैं। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। हरिद्वार के अलावा, कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे नासिक में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के प्रसिद्ध संगम पर इलाहाबाद में और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में आयोजित होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, हरिद्वार उन चार स्थानों में से एक है जहां देवताओं और राक्षसों के युद्ध के दौरान अमृत गिरा था, और इसीलिए इस भूमि को पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी के जल में स्नान करना अमरत्व प्राप्ति का प्रतीक है, और इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले में कई अखाड़े भाग लेते हैं, जिनमें नागों को सबसे पहले स्नान करने का अवसर मिलता है। हरिद्वार का यह कुंभ मेला विश्वभर के सभी हिंदुओं के लिए सबसे शुभ धार्मिक आयोजनों में से एक होने के साथ-साथ हमेशा एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। यह विश्व भर से आगंतुकों, मीडिया, फिल्म निर्माताओं, संवाददाताओं, लेखकों और आम जिज्ञासु दर्शकों को आकर्षित करता है। हरिद्वार कुंभ मेले के नाम विश्व में सबसे बड़े मानव जमावड़ों में से एक होने का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि 14 अप्रैल 2010 को अकेले लगभग 1 करोड़ लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया था।

अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बाल यौन शोषण मामले में एफआईआर

यूपी पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2-3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है.

अशोक तिवारी
लखनऊ ब्यूरो प्रमुख

प्रयागराज की पौक्सो कोर्ट ने झूसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिए थे कि वो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पौक्सो कानून की धाराओं के तहत इन अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करे. पौक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में पुलिस से कहा था कि वो पौक्सो एक्ट के तहत निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करे. साथ ही कोर्ट ने सर्वाइवर की पहचान और सम्मान की सुरक्षा करने का भी आदेश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इन



निर्देशों को तुरंत पूरा करते हुए कोर्ट को बताया जाए.

शंकराचार्य ने क्या कहा?

कोर्ट के इस आदेश के बाद शंकराचार्य ने दावा किया है कि यह मामला झूठा है. उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और दोषियों को सजा मिल सकेगी. इसलिए केस दर्ज होना और आगे की जांच होना जरूरी है. कोर्ट को इस पर जल्दी काम करना चाहिए और ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मामले को देख रहे हैं. गवाही दर्ज हो और जल्द फैसला लिया जाए. जो गलत है वह गलत ही

रहेगा, जो झूठा केस दर्ज किया गया है वह आखिरकार झूठा साबित होगा. वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत की मांग वाली याचिका लेकर कोर्ट गए शख्स का भी बयान सामने आया है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है. प्रथम दृष्ट्या हमें न्याय मिला है. छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे. कोर्ट ने उन साक्ष्य की जांच करने के भी आदेश दिए हैं, जो हमने दिए थे.

योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तकरार





इसी साल जनवरी में उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में एक विवाद की वजह से चर्चाओं में थे. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

18 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में स्नान करने जा रहे थे. इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद वो धरने पर बैठ गए थे. वो पहले मांग कर रहे थे कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तभी वो स्नान करेंगे. अविमुक्तेश्वरानंद

ने 28 जनवरी को ये घोषणा की कि वो इस माघ मेला में स्नान नहीं करेंगे और उन्हें दुखी मन से मेले से जाना पड़ रहा है. उन्होंने मीडिया को जारी बयान में ये दावा किया है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई शंकराचार्य बिना

स्नान किए मेला छोड़कर गए हों. इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था. हालाँकि इस

मामले में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी. लेकिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने



उनसे स्नान करने की अपील की थी. सीएम योगी ने इस मामले में किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग कालनेमि हैं. सिएम ने यह बयान हरियाणा के सोनीपत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया था. उन्होंने कहा था, ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन

धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे. हमें उनसे सावधान होना होगा. हमें उनसे सतर्क रहना होगा. योगी ने 14 फरवरी को यूपी विधानसभा में कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं

बन सकता है. उन्होंने राज्य में कानून के शासन पर जोर देते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी पीठ के आचार्य के रूप में कहीं भी वातावरण खराब नहीं कर सकता. इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, नजीर है, आदित्यनाथ के ऊपर 40 से

ज्यादा मुकदमे थे और जब वह मुख्यमंत्री बने तो सभी मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए. ये कैसा कानून का पालन है? ये क्या कानून में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे? ये कहाँ लिखा है? उन्होंने

कहा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर आपने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूँ. अगर आप कानून का पालन करने वाले हैं तो 45 केस और उनका कोर्ट में सामना करिए.



48 घंटों में हो रही मौतों से हरियाणा गांव में छाया मातम



संजय सिन्हा हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

हरियाणा के पलवल जिले का छांयसा गांव में पिछले कुछ हफ्तों से अचानक बीमारी, तेजी से बिगड़ती सेहत से लोगों की मौतें हो रही हैं। 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच छांयसा में कम से कम 15 मौतें हुईं, इनमें चार नाबालिग बच्चे हैं। प्रशासन ने इन मौतों में से कम से कम सात को पीलिया और हेपेटाइटिस बी से जोड़ा है। अब छांयसा की हवा में सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि अनिश्चितता और डर भी घुले नजर आते हैं। सुबह की ठंडी हवा में फज्र की अजान की आवाज धीरे-धीरे आ रही थी। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठी आशूबी की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ घंटे पहले तक उन्हें यकीन था कि उनका 14 साल का बेटा शारिक जल्द ठीक हो जाएगा। उनके लिए आखिर यह सिर्फ बुखार ही तो था। लेकिन उस सुबह डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वह धीमी आवाज में कहती हैं, प्लात तक तो ठीक था, सुबह देखा तो डॉक्टर पंपिंग कर रहे थे। चौदह साल के शारिक 25 जनवरी को अचानक बीमार पड़ने से पहले तक बिल्कुल ठीक थे। बुखार आने के 48 घंटों के भीतर ही उनकी मौत हो गई। शारिक का लिवर फेल हुआ था।

गांव में डर और सवाल

यहां लोगों की बातचीत में 'मौत और

'डर' जैसे शब्द बार-बार सुनाई देते हैं। यहां लोगों की बातचीत में श्मौतश् और श्दरश् जैसे शब्द बार-बार सुनाई देते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर छांयसा गांव की आबादी करीब छह हजार है। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहां बड़े लोगों की बातचीत में श्मौतश् और श्दरश् जैसे शब्द बार-बार सुनाई देते हैं। जनवरी



के आखिरी हफ्ते से गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ने लगे। परिवारों के मुताबिक, शुरुआत अक्सर बुखार से होती थी, कुछ को पेट दर्द, कुछ को पीलिया जैसे लक्षण होते थे फिर अचानक हालत बिगड़ जाती थी। 11 साल के हुजैफा की मां बताती हैं, एक दिन बुखार आया था। दवा ली तो ठीक लग रहा था। उसी रात तबियत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचे तो बोले लिवर काम नहीं कर रहा। डॉक्टरों ने लिवर

ट्रांसप्लांट की सलाह दी तो हुजैफा की मां तुरंत तैयार हो गईं। लेकिन उसके लिए भी वक्त नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह कहती हैं, मैं अपना लिवर देने को तैयार थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा अब नहीं बच पाएगा।

48 घंटों में मौत और बढ़ती बेचौनी

टिन पड़े बिना प्लास्टर के अधबने मकान के खुले दरवाजे से मोटा पर्दा पड़ा दिखाई देता है। 22 साल के दिलशाद की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी बीवी अब इद्दत कर रही हैं। दिलशाद चेन्नई में काम करते थे और 9 फरवरी को बुखार की हालत में घर लौटे। परिजनों में पहले गांव में इलाज कराया और फिर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले गए। उनकी मां कहती हैं कि आईसीयू में रखा, 48 घंटे में खत्म हो गया सब। उनके पिता हकीमुद्दीन कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बुखार आए और चार-पांच

दिन में आदमी खत्म। दिलशाद का भी मरने वाले बाकी लोगों की ही तरह लिवर फेल हुआ था। शहनाज के 11 साल के बेटे हुजैफा की भी लिवर फेल होने से मौत हो गई गांव में मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग बातें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंद्रह तो कुछ बीस तक मौतों का दावा करते हैं। इस गांव में 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच गांव में कम से कम पंद्रह मौतों का पता चला है,



जिनमें कई बुजुर्ग थे जिनकी मौत घर पर ही बीमारी से हुई। लेकिन प्रशासन के अनुसार, कम से कम सात मौतें अचानक बीमार पड़ने से हुई हैं और अभी तक इन मौतों के स्पष्ट कारण की पुष्टि नहीं की जा सकती।

प्रशासन क्या कर रहा है?

सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा के अनुसार करीब 1100 सैंपल लिए गए हैं। 2100 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग की गई है। इमेज कैंप्शन, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा के अनुसार करीब 1100 सैंपल लिए गए हैं। 2100 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 फरवरी से गांव में हेल्थ कैंप लगाया है और अब तक एक हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि जांच की जा सके। सहायक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा बताते हैं कि करीब 1100 सैंपल लिए गए हैं। 2100 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग की गई है। वह कहते हैं कि हमने गांव में क्लोरीनेशन भी किया है, बीमारी से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी 209 लोगों को लगा दी है। इसके अलावा पानी की जांच भी की जा रही है, हेवी मेटल टेस्ट किए गए हैं। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ कहते हैं कि अब तक सात मौतें हुई हैं, मरने वालों में चार केस हेपेटाइटिस-बी पॉजिटिव थे। इसके अलावा जांच के दौरान गांव में 17 हेपेटाइटिस-सी के कंफर्म केस मिले हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन प्रशासन के दावों और गांव के लोगों की बेचोनी के बीच एक फासला महसूस होता है। गांव वाले पूछ रहे हैं, अगर बीमारी पहले से थी, तो अचानक इतनी मौतें क्यों हुईं?

गांव के पास से गुजरती गुरुग्राम नहर का पानी काला, बदबूदार है। छांयसा में मीठा भूजल नहीं है। गांव में लगभग हर घर के बाहर पानी के टैंक दिखते हैं। शारिक की मां आशूबी एक बाल्टी से लौटे में पानी निकालकर दिखाते हुए कहती हैं कि पीने का पानी खरीदना पड़ता है। वह गांव में एक टैंक से रोजाना दो बाल्टी पानी भरकर लाती हैं। घरों तक पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसमें पीने का पानी नहीं आता। दिलशाद के पिता हकीमुद्दीन कहते हैं कि मौतों की एक वजह पानी भी हो सकता है। हमारे गांव में लोग बासी पानी पीते हैं, एक बार टैंक में पानी डलवाते हैं और महीना भर उसी पर गुजारा करना होता है। यही नहीं, छांयसा गांव के आस-पास भरा पानी भी एक बड़ी समस्या है। गांव के बाहर एक बड़े इलाके में बारिश का पानी ठहरा है। गांव के पास से गुजरती गुरुग्राम नहर पर खड़े होकर पानी को देखते हुए साफ समझ आता है कि लोग चिंतित क्यों हैं। पानी काला और बदबूदार है। छांयसा और आसपास के गांवों की पचास हजार एकड़ जमीन बारिश के पानी में डूबी है। स्थानीय कार्यकर्ता रामेश्वर कहते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल आता है। अगर पानी में हाथ डाल दो तो खुजली हो जाती है। छांयसा और आसपास के गांवों की पचास हजार एकड़ जमीन बारिश के पानी में डूबी है। पानी यहां से बाहर निकल ही नहीं पाता है। क्या इस पानी का लिवर की बीमारी से कोई संबंध है? प्रशासन अभी इसकी पुष्टि नहीं करता। हालांकि, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ कहते हैं, हमने पानी के टेस्ट कराए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। गांव के बाहर बरसाती पानी जमा है। खेतों में पानी भरा है। कुछ किसान बताते हैं कि खेती प्रभावित हो चुकी है। एक स्थानीय व्यक्ति कहते हैं कि 12 महीने पानी खड़ा रहता है। खेती खत्म हो गई। गांव की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय बदलाव बीमारी की कहानी में एक नई परत जोड़ते हैं।



खेजड़ी के पेड़ काटने के खिलाफ गांव की महिलाएं सिर कटाने को तैयार

रानू पाठक

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के खिलाफविशेषकर बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत भारी विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में पेड़ काटे जाने के खिलाफ गांव की महिलाएं अपना सिर कटवाने तक को तैयार हैं। हाल ही में गांव के करीब 500 लोग अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद बीकानेर के पर्यावरण बचाओ महापड़ाव में लोगों ने अनशन तोड़ दिया लेकिन महापड़ाव स्थल पर धरना लगातार जारी है। आंदोलन कर रहे लोगों की मांग है कि पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर रोक लगाई जाए। आंदोलनरत लोग बिना लिखित आश्वासन के मानने को तैयार नहीं हैं। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, पशुपालन, और जीवन व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। 730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई समेत 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था और सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि प्रकृति और समाज के रिश्ते की अमिट मिसाल बन गया था। अब सौर ऊर्जा प्लांट्स के लिए खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के खिलाफ वही चेतावनी फिर गूंज रही है, सिर कटा देंगे लेकिन खेजड़ी नहीं कटने देंगे। आंदोलन के चौथे दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून बनाने की घोषणा की है। हालांकि आंदोलनकारी लिखित आश्वासन मिले बिना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं।

महापड़ाव और सामूहिक आमरण अनशन



पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर समेत कई इलाकों से लाखों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की खबरें आ रही थीं। स्थानीय स्तर पर लगातार पर्यावरण प्रेमी खेजड़ी की कटाई का विरोध कर रहे थे। सरकार पर इस विरोध को नजरअंदाज करने और विकास के नाम विनाश करने का आरोप लगाते हुए दो फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव बुलाया गया। खेजड़ी बचाने के लिए इसमें सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी जुटे। जिला कलेक्टर कार्यालय के पास एक खेजड़ी का पेड़ मौजूद है, इसकी छांव में पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी खड़े हैं। इसके सामने जारी आमरण अनशन के तीसरे दिन लोगों की तबियत बिगड़ने लगी थी। कुछ को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। यह सामूहिक आमरण अनशन महंत स्वामी सच्चिदानंद आचार्य के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आचार्य ने कहा कि यह सरकार की दोहरी नीति है कि एक पेड़ मां के नाम पर लगाया जा रहा है और दूसरी

ओर दादा-दादी के नाम से लगाए गए सैकड़ों साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं।

सोलर प्लांट और खेजड़ी के पेड़

बीकानेर-जयपुर हाइवे पर दोनों तरफ कई जगह सोलर प्लांट लगे हैं। इनमें सिर्फ सोलर प्लेटों की एक काली चादर दिखाई पड़ती है। इन प्लांटों के पास कटे हुए पेड़ों के अवशेष दिखाई देते हैं। ये हालात पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में हैं। महापड़ाव और आमरण अनशन में शामिल महिलाओं की तादाद भी कम नहीं है। वह अपने परिवार और बच्चों को छोड़ कर खेजड़ी बचाने के लिए घरों से निकल आई हैं। अनशन कर रही इंद्रा बिश्नोई कहती हैं कि खेजड़ी के लिए हम सब अमृता देवी बिश्नोई की तरह बन कर बैठी हैं, जो उन्होंने किया वही हम करेंगे। हम सिर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खेजड़ी नहीं कटने देंगे। पर्यावरण संघर्ष समिति के संयोजक परसराम बिश्नोई की इस महापड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। महापड़ाव स्थल पर उन्होंने कहा, 296 साल बाद अब फिर हम वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। वह कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी के नाम पर एक कानून लाई। इस कानून में धीरे-धीरे संशोधन करके बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में सैकड़ों साल पुराने लाखों पेड़ काट दिए। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है, मजबूरन हमें महापड़ाव करना पड़ा है। सरकार जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमांच और उलटफेर की कोई कमी नहीं रही.



श्वेतांक वर्मा

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

चाहे ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना हो, या पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के बायकोर्ट को लेकर विवाद, या न्यूजीलैंड का खिताब के प्रबल दावेदार दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में मात देना, फैंस कई रोमांचक और दिल को छू लेने वाले पलों के गवाह बने. लेकिन इन सबके इतर जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वो थे एसोसिएट देश. जिन्होंने भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों की मौजूदगी के बावजूद बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. क्रिकेट इतिहास में एसोसिएट देशों की उपस्थिति पर अक्सर मिक्सड रिएक्शन देखने को मिलते हैं. क्या वे केवल संख्या बढ़ाने के लिए हैं, या वे वास्तव में इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं? यह बहस लगभग हर वर्ल्ड कप में देखने को मिलती है. अगर भारत और श्रीलंका में हुए टी-20 वर्ल्ड कप को देखें तो, आठ एसोसिएट देशों ने सिर्फ इसमें हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि एक अलग छाप भी छोड़ी. अमेरिका के भारत को हार के कगार पर ६ कैलने से लेकर, फहीम अशरफ की पारी से पहले नीदरलैंड्स के पाकिस्तान को संकट में डालने तक. कनाडा के 19 वर्षीय युवराज सिंह समरा के न्यूजीलैंड के खिलाफ 110 रन बनाकर टी-20 या वनडे वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र वाला खिलाड़ी बनने तक, ये टूर्नामेंट साहसिक और प्रेरणा देने वाली कहानियों से भरपूर रहा.

लंबा रास्ता

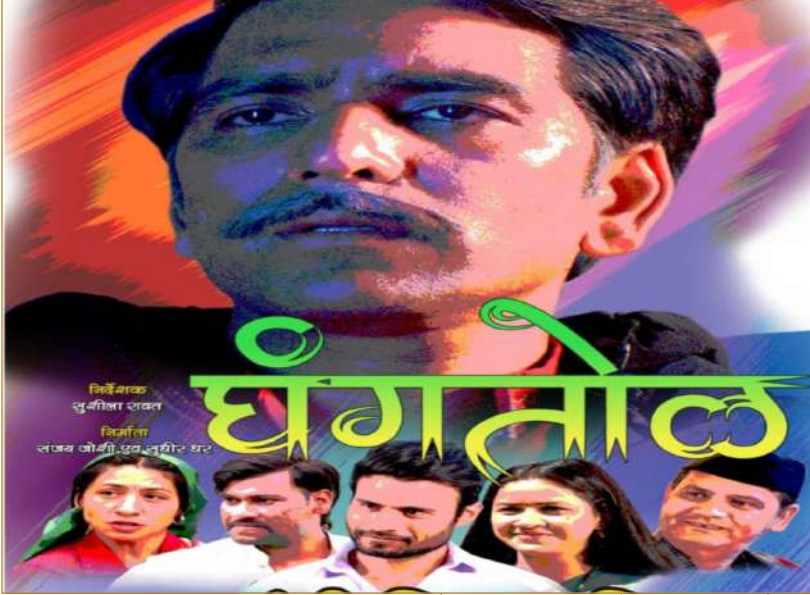
साल 1965 में, फिजी और अमेरिका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (तब इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस) के पहले एसोसिएट सदस्यों में शामिल थे. उसके बाद से ही एसोसिएट सदस्यों की संख्या

में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 2026 तक, आईसीसी के यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में 90 से अधिक एसोसिएट सदस्य हैं. 2026 टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान नीदरलैंड्स, कनाडा और पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही इटली को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एमस्टेलवीन स्थित वीआरए स्टेडियम नीदरलैंड्स टीम का बेस था, लेकिन ये पूरी तरह से बर्फ ढका हुआ था. वहीं कनाडा को भी इसी तरह की भारी सर्दी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण खिलाड़ियों को इंडोर में ही रहना पड़ा. लेकिन इसके समाधान भी अनूठे रहे. टीमों को अलग-अलग हिस्सों में बांटना और विदेश में ट्रेनिंग करना. नीदरलैंड्स और कनाडा ने श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और भारत में टीमें भेजीं, जहां उचित सुविधाएं और ज्यादा ठंड नहीं थी. नीदरलैंड्स टीम के मैनेजर जॉन वैन व्लिएट ने बर्फ से ढके मैदानों की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, हालात को देखते हुए हमें तैयारी के लिए विदेश जाना पड़ा. हमने एक दल को दक्षिण अफ्रीका भेजा, दूसरे को भारत. आखिरकार, वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले हम सभी चेन्नई में जमा हुए और फिर कोलंबो चले गए.

टूर्नामेंट के दौरान नीदरलैंड्स के मैच नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किए गए. कुछ साल पहले तक इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था. नीदरलैंड्स और इटली जैसे फुटबॉल, हॉकी और साइकिलिंग के शौकीन देशों में क्रिकेट अक्सर नॉन-प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलते हैं. वो वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिना वेतन के छुट्टी लेते थे या यहां तक कि अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे देते हैं. नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन ने कहा, नीदरलैंड्स में क्रिकेट के प्रशंसक उतने

ज्यादा नहीं हैं, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल है. लेकिन खेल निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है. उम्मीद है कि इस साल यूरो टी-20 स्लैम का आयोजन होगा. मुझे लगता है कि देश में क्रिकेट का आगे बढ़ना जारी रहेगा. कनाडा की कहानी भी अलग नहीं है. ऐसा देश जहां की स्थितियां और कल्चर आइस हॉकी के अनुरूप हों, वहां क्रिकेट के लिए अपनी जगह बना पाना बेहद मुश्किल है. कनाडा के विकेटकीपर बल्लेबाज श्रेयस मोवा ने कहा, हमारे लिए गर्मियों की शुरुआत मई में होती है और सितंबर या अक्टूबर तक चलती है. अगर आप खुशकिस्मत हैं तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक क्रिकेट खेल सकते हैं. उसके बाद हम इंडोर प्रैक्टिस करते हैं. हम नेट प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन वहां कोई असल मैच जैसे हालात नहीं होते. एक खिलाड़ी के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि टीम के लिए मैच कैसे जीतना है, दबाव को कैसे झेलना है. लेकिन ये चीजें हमें इंडोर प्रैक्टिस में नहीं मिलतीं. श्रेयस मोवा कर्नाटक से हैं और 2016 में वो कनाडा शिफ्ट हुए. 32 साल के श्रेयस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं. संयुक्त अरब अमीरात की टीम कई संस्कृतियों के मिलन को दिखाती है. भारत, पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई प्रवासियों से बना समूह एक ही ड्रेसिंग रूम में एकजुट है. भारत, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान को कोचिंग दे चुके लालचंद राजपूत अब यूएई की टीम के मुख्य कोच हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को साथ लाने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए कड़ी मेहनत की है. वो कहते हैं, एक कोच के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात है टीम का एकजुट होना और ड्रेसिंग रूम में आपसी सौहार्द. जब वे मैदान पर उतरते हैं, तो वे एक ही टीम के रूप में खेलते हैं.

गढ़वाली फिल्म घंगतोल 6 मार्च को दिल्ली और एनसीआर के 11 सिनेमाघरों में रिलीज हुई



सुनील नेगी

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्म श्रृंगतोल, जिसका अर्थ है भ्रम, 6 मार्च, 2026 को देश भर के तेरह सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसका निर्माण जोधा फिल्म्स, संजय जोशी और सुधीर धर ने किया है और निर्देशन उत्तराखंड सिनेमा की पहली महिला निर्देशक सुशीला रावत ने किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर (नोएडा और गाजियाबाद) में यह फिल्म पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में ग्यारह सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह पहली बार है कि कोई गढ़वाली फिल्म राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में इतने बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है। यह फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा है जो रिवर्स माइग्रेशन का सामाजिक संदेश देती है और इसमें सौ से अधिक कलाकारों ने अभिनय किया है, जिससे यह सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। उत्तराखंड फिल्म उद्योग ने इस दशक में काफी प्रगति की है और उत्तराखंड तथा उत्तराखंड की आबादी वाले देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में फिल्मों सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई

हैं। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने में सरकारी सब्सिडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्माता संजय जोशी ने बताया कि घंगतोल ने देहरादून और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में अच्छा कारोबार किया। उनकी पिछली फिल्म चक्रव्यूह गढ़वाली, कुमाऊँनी और नेपाली भाषाओं में डब होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकी। हालांकि, माना जा रहा है कि वर्तमान फिल्म श्रृंगतोल अच्छा कारोबार कर रही है और दर्शकों द्वारा पसंद की जा रही है क्योंकि इसकी पटकथा, संगीत, गीत, प्राकृतिक सौंदर्य और सिनेमैटोग्राफी उत्कृष्ट हैं। फिल्म की शूटिंग गढ़वाल, उत्तराखंड के शांत वातावरण और खूबसूरत स्थानों में की गई है, जिसमें सुशीला रावत का

निर्देशन बेहद सराहनीय है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार हैं। विशंभर के रूप में कुलदीप असवाल, भास्कर के रूप में जितेन बिष्ट, जाहन्वी के रूप में सर्पती रावत, खीम दा के रूप में पदमेंद्र रावत, विक्रम प्रधान के रूप में विकास खत्री, आभा के रूप में नीलम रावत, चंद्र मोहन के रूप में अजय सिंह बिष्ट, नीरजा के रूप में किरण लखेरा इस्टवाल, पीतांबर दत्त के रूप में खुशल सिंह बिष्ट, विभा के रूप में प्रज्ञा रावत मालती के रूप में वैभवी, चंदन के रूप में दक्ष दिगंबर के रूप में सुशील पुरोहित। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीत निर्देशक राजेंद्र चौहान ने दिया है। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित पुरुष और महिला गायक नरेंद्र नेगी, अनुराधा निराला, कल्पना चौहान, रोहित चौहान और विवेक नौटियाल ने इस फिल्म के प्रभावशाली गीतों को अपनी सुरीली आवाज दी है। इन गीतों के गीत श्रीमती सुशीला रावत, डॉ. शिवानंद नौटियाल, राजा बिष्ट और डॉ. सतीश कालेश्वरी ने लिखे हैं। फिल्म के छायांकन ध्रुव त्यागी और संपादन पुष्कर भरत पंत ने किया है। ध्वनि अभियंता जितेंद्र पाठक हैं, जबकि पटकथा संजय जोशी और सुशीला रावत ने संयुक्त रूप से लिखी है। मेकअप लकी मुस्तकीम ने किया है और पृष्ठभूमि संगीत विजय कपूर ने दिया है। फिल्म के संपूर्ण निर्माण का नियंत्रण प्रोडक्शन इंचार्ज कुशल सिंह बिष्ट ने संभाला है, जो स्वयं एक प्रमुख अभिनेता हैं।





"First, we eat Maharani Rice,
Then we do everything else."

VEG BIRYANI





तालचेर कनिहा
TALCHER KANIHA

ODISHA'S LARGEST POWER STATION

With an installed capacity of **3010 MW** and making significant contributions to the lives of communities surrounding the station.



TALCHER SUPER THERMAL POWER STATION
Kaniha, PO: Deepshikha, Dist : Angul, Odisha - 759147

[f /ntpc1](#) [/ntpcld1](#) [/ntpclimited](#) [in /company/ntpc](#) [/ntpclimited](#)

Leading the Power Sector